This Bill was introduced in Rajya Sabha as far back as 27th July, 1992. More than four years have elapsed already and the Bill is now before us for final consideration and passing. What is surprising me, and I think everybody else in the House, is that the amendment to section 28 of the Indian Contract Act was necessitated on account of the recommendations made by the Law Commission's report which it made in 1984. The exact date is 6th April, 1984 when the 97th report of the Law Commission of India was submitted. Thereafter, the Ministery of Law took more than four years to come forward saying that it had accepted the recommendations of the Law Commission in principle.

Prior to that even in this august House an Unstarred Question was put and the Government of India had given an assurance that they would come forward soon with an amendment. They took more than four years to accept the recommendations, that too in principle. Thereafter, I feel rather sorry to say that the Government of India did not fulfil the assurance that the Minister had given to this august House. It was only in 1991 that the Committee on Government Assurances summoned the Department of Justice and Legal Affairs and it was only thereafter that the process, in fact, started. Ultimately, way back in 1992, the Cabinet approved the amendment and, thereafter, in 1994 the Bill was presented.

Madam, I have given these dates delibrately to show how casually the Government of India took this amendment. Even in the objects of the Bill that have been mentioned by the hon. Minister, it has been said, "It is felt that Section 28 of the Indian Contract Act, 1872 should be amended as it harms the interests of the consumers dealing with big corporations and causes serious hardship to those who are economically disadvantaged". The Standing Committee also said in its report, "It harms the interests of the consumers dealing with big corporations and causes serious hardship to those who are economically disadvantaged". Who are those people—the big corporations, the MNCs, the economically disadvantaged people or the people at large? Most of the people that are going to be benefited by this amendment are the poor people, the common people, middle class people. Madam, many of our people take insurance policies. It may be life insurance, insurance against accidents or other policies. Because of non-implementation of Section 28, these people have been put to a great disadvantage; And the people who have got the advantage because of this are the big corporations, the MNCs and the insurance companies. Section 28 has certainly put a distinction between the remedy and the right. It will certainly give advantage to the weaker sections and the people at large. What I want to emphasise is that the Government had taken this amendment in a very casual manner. It is now more than 12 years that the Law Commission's report was presented and today this Bill has come for final consideration. I would not like to add more to the delay in the passing of the Bill. So, with these remarks, I conclude.

SHRI SANATAN BISI (Orissa): Madam, the Bill has already been delayed. I would only like to make a small submission to the hon. Minister. Since the Bill relates to economic justice, avoidance of hardship to the consumer, I would like to know whether there are certain impediments so far as Section 28 of the Indian Contract Act is concerned...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): Mr. Bisi, It is 2.30, and we have to take up Private Members' Business. I know that you have just started your speech, but you will continue your speech next time.

SHRI SANATAN BISI: Thank you, Madam.

THE VICE-CHAIRMAN (Shrimati Kamla Sinha): Mr. Minister, now we have to take up Private Members' Business. Shrimati Anandiben Jethabhai Patel is to speak on Resolution No. 1.

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTION

RE: Free and Compulsory Education for children up to the age of 14 Years.

श्रीमती आनन्दीबेन जेठाभाई पटेल (गुजरात): उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित संकल्प उपस्थित करती हूं कि:–

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हमारे संविधान के

नीति निर्देशक सिद्धान्तों में 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है लेकिन स्वतंत्रता के 50 वर्षों के बाद भी इस संबंध में सरकार के उदासीन और उपेक्षित दृष्टिकोण के कारण हमारे देश में लाखों बच्चे प्राथमिक शिक्षा से भी वंचित हैं और इसलिए आज हम पाते हैं कि:-

(i) देश में विशेषकर ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक और माध्यमिक सरकारी स्कूलों की संख्या अपर्याप्त है;

(ii) तेजी से बढ़ रहे गैर सरकारी संस्थानों/स्कूलों, जो कि प्राथमिक स्तर पर ही भारी शिक्षण शुल्क और चंदा ले रहे हैं, पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है जिसके परिणामस्वरूप शिक्षा के स्तर में भारी असमानता व्याप्त हो गई है तथा गरीब और यहां तक कि मध्यमवर्गीय समाज के माता पिता भी अपने बच्चों को इन स्कूलों में भेजने में असमर्थ हो गये हैं; और

(iii) प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने वाले गैर-सरकारी संगठनों को उचित सहायता/प्रोत्साहन की कमी है,

यह सभा वर्तमान स्थिति को गंभीरता से नोट करती है और सरकार से आग्रह करती है कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल उपचारी उपाय करे कि इस देश का प्रत्येक बच्चा हमारे संविधान की भावना के अनुसार नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करे।

उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है।

मैं सदन का और सरकार का ध्यान देश की एक गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। आज गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प में मेरा संकल्प आया है। मैं प्राथमिक शिक्षा की दयनीय स्थिति की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

महोदया, संविधान में 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, लेकिन स्वतंत्रता के 50 वर्षों के बाद भी इस संबंध में सरकार का दृष्टिकोण उदासीन और उपेक्षित रहा है और इसी कारण देश के लाखों बच्चे प्राथमिक शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। सरकार प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने में निष्फल हो गई है। सरकार का दायित्व है कि प्राथमिक शिक्षा में सुधार लाए। प्राथमिक शिक्षा को सफल बनाने के बारे में सरकार किस तरह निष्फल हुई है, वह मैं सरकार को और सदन को बताना चाहती हूं तथा अनिवार्य और नि:शुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कुछ सुझाव भी देना चाहती हूं।

महोदया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि 14 साल की आयु तक के सभी बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना सरकार का दायित्व है। यह व्यवस्था संविधान के लागू होने से 10 वर्ष की अवधि में लागू हो जानी चाहिए थी, अर्थात सन् 1960 तक, लेकिन आज तक यह कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। 1986 में हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई तथा 1992 में कार्य योजना बनाई गई और फिर इस देश को वचन दिया गया कि 21वीं शताब्दी के प्रारम्भ होने से पूर्व 14 साल के सभी बच्चों को संतोषजनक स्तर की शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसके लिए 8वीं पंचवर्षीय योजना में तीन बातों पर ध्यान केन्द्रित किया गया-बालकों और अनुसूचित जाति, जनजाति के बच्चों सहित सभी बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध करना, एक किलोमीटर पैदल की दूरी तक प्राथमिक स्कूल की व्यवस्था करना, प्राथमिक शिक्षा बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों, काम-काजी बच्चों तथा स्कूल में नहीं जाने वाले बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करना और प्राथमिक स्कूलों में सुधार करना। अगर इस नीति को गंभीरता से लागू किया गया होता तो आज देश की 80 से 90 प्रतिशत जनता शिक्षित होती, लेकिन आश्चर्य की बात है कि आजादी के समय देश की जो जनसंख्या थी आज उससे ज्यादा जनसंख्या देश में निरक्षरों की है। सरकार आदर्शवाद के आधार पर अपनी शिक्षा नीति निर्धारित करती है, उसने देश की विशाल जनसंख्या और सीमित साधनों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। एक ओर देश में बच्चों की संख्या बढ़ रही है, शिक्षकों की संख्या भी बढ़ रही है तो दूसरी ओर शिक्षा का सरकारी बजट लगातार घटता गया है।

शिक्षा मंहगी हो रही है। प्राथमिक शिक्षा की तरफ केन्द्र और राज्य सरकारों ने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। प्राथमिक पाठशालाओं की संख्या 25 साल में 2 लाख बढ़ी है लेकिन इसके अनुपात में शिक्षकों की संख्या नहीं बढ़ी। पाठशालाओं की संख्या बढ़ती गई लेकिन सरकार के बजट में प्राथमिक शिक्षा पर होने वाला खर्च घटता गया। लोगों ने यह आशा की थी कि प्राथमिक शिक्षा पर जो धन व्यय किया जाता है, उसमें कोई कमी नहीं आएगी, उत्तरोत्तर धन की राशि बढ़ती जाएगी लेकिन सरकार ने हरेक पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक शिक्षा के बजट का प्रतिशत घटा दिया है। पहली पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के बजट का 58 प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा के लिए रखा गया। दूसरी योजना में 35 परसेंट रखा गया। तीसरी योजना

में यह घटकर 25 परसेंट रह गया। चौथी योजना में 30 परसेंट रखा गया। फिर थोड़ा सा बढ़ाकर पांचवीं योजना में 32 परसेंट रखा गया और छठी योजना में 36 परसेंट रखा गया। इस तरह से प्राथमिक शिक्षा पर जो खर्च करना चाहिए, वह नहीं होता है। इसकी वजह से ये सारी बीमारियां बढ़ी हैं।

महोदया, प्राथमिक शिक्षा के लिए जो धन दिया जाता है, उसमें से 95 प्रतिशत धन शिक्षकों के वेतन और प्रशासन में खर्च हो जाता है। जो कुछ बचता है उसमें से स्टेशनरी का खर्च, घूमने-फिरने का खर्च, खेल-कूद का खर्च, वैज्ञानिक उपकरण खरीदने का खर्च, चार्ट्स का खर्च निकाला जाता है। पर चूंकि धन की कमी रहती है इसलिए न वैज्ञानिक उपकरण खरीदे जाते हैं, न खेल-कूद की व्यवस्था पाठशालाओं में होती है।

महोदया, सरकार ने प्राथमिक शिक्षा का खर्च कम तो कर दिया लेकिन दूसरी ओर माध्यमिक, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा का खर्च बढ़ा दिया। प्राथमिक शिक्षा के खर्च को काटकर इसमें लगाया गया है। मेरी समझ में नहीं आता कि प्राथमिक शिक्षा के खर्च को काटकर इसमें क्यों लगाया गया है? प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने के बाद ही माध्यमिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा की शुरूआत होती है। महोदया, भारत में शिक्षा राजनीति का शिकार बन चुकी है। शिक्षा की व्यवस्था करना, स्कूल चलाना पहले कर्तव्य समझा जाता था लेकिन अब यह एक व्यवसाय बन चुका है। शिक्षा को पैसा कमाने का साधन मान लिया गया है। प्राइवेट स्कूल खूब चल रहे हैं। वहां हजारों रुपए डोनेशन देकर बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। ऐसे भ्रष्ट स्कूलों को बंद करने का साहस किसी में नहीं है। स्कूल तो सिर्फ कागज पर भी चलते हैं। पंचायतों और नगरपालिकाओं पर इन स्कूलों के भवनों की देखभाल की जिम्मेदारी है लेकिन धन के अभाव में भवन गिर जाने से बच्चे मारे भी जाते हैं। महोदया, हमारे देश की जनसंख्या 92 करोड़ से अधिक है और इसमें 14 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या लगभग 30 करोड़ है। सरकार का दावा है कि 98 प्रतिशत बच्चे प्राथमिक शिक्षा लेते हैं लेकिन यह दावा गलत है। वास्तविक यह है कि प्राथमिक पाठशालाओं में जाने वाले बच्चों की संख्या 12 करोड़ से अधिक नहीं है। महोदया, 1993-94 में एक सरकारी रिपार्ट में उनकी संख्या 10 करोड़ 80 लाख दिखाई गई है। यानी 14 साल से कम उम्र वाले बच्चे स्कूल से बाहर हैं। सरकार को 1960 तक यह लक्ष्य पूर्ण कर लेना चाहिए था लेकिन सरकार इसमें भी विफल रही है। अब इस सदी के अंत तक या अगली सदी के 5 वर्षों में सरकार पूरे देश को साक्षर बनाने का दावा कर रही है।

मैडम, 1986 में हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी और इसमें 1992 में कुछ सुधार किया गया। देश के 14 साल की उम्र के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य रूप से देने का प्रावधान था लेकिन आज तक सरकार सभी बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकी है इसके कई कारण हैं। प्राथमिक शिक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में साधन होने चाहिएं। क्या स्कूल के भवन पर्याप्त संख्या में हैं? वर्ग खण्ड में बच्चे बैठ सकें क्या ऐसा है? वर्ग खण्ड की छत ठीक-ठाक है? बारिश के समय पर पानी छत में से गिरता है तो चार मास तक स्कूल बन्द हो जाते हैं। चालीस साल से स्कूलों की मरम्मत किसी ने नहीं की है। गुजरात में भाजपा की सरकार के समय में नये वर्ग खण्ड बनाने के लिए बजट में लाखों रुपये रखे गये हैं। पाठशालाओं में क्लर्क और प्युन नियुक्त करने की कोई आवश्यकता सरकार को नहीं लगती है? पाठशालाओं में क्लर्क नहीं होने से सारा काम शिक्षकों को करना पड़ता है जिसकी वजह से शिक्षण कार्य पर प्रभाव पड़ता है और पाठशालाओं में शिक्षा कम होती है। इससे दुगुना नुकसान हो रहा है। सरकार को पाठशाला और पाठशाला के मैदान की सफाई के लिए और अन्य कार्य करने के लिए प्युन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्युन के अभाव में यह कार्य भी शिक्षक कर रहे हैं। पाठशालाओं में कम्पाउन्ड न होने से और सिक्योर्टी की कोई व्यवस्था न होने से रात के समय पाठशालाएं धर्मशालाओं में बदल जाती हैं। पाठशालाओं में असामाजिक प्रवृत्तियां चलती रहती हैं। वहां पर गाय-भैंस बैठी रहती हैं। वहां पर जुआ और दारू के अड्डे शुरू हो जाते हैं, वहां पर तोड़-फोड़ होती है, चोरी होती है।

मैडम, केन्द्र सरकार ने प्राथमिक पाठशालाओं में टी. वी. और रेडियो भेज दिये हैं। दोपहर के समय टी.वी. और रेडियो पर शैक्षणिक कार्यक्रम इसलिए आते हैं कि उन्हें बच्चे देख सकें। लेकिन आप वहां पर रेडियो और टी.वी. का सर्वे कीजिए। आप देखेंगे कि कई स्कूल ऐसे हैं जहां से रेडियो और टी.वी. गायब हो गये हैं। पाठशालाओं में टी.वी. और रेडियो चलाने के लिए बिजली चाहिए तो जब गांवों में ही बिजली नहीं होती हैं तो बिजली के ये साधन कैसे चल सकते हैं? यदि वहां पर बिजली है तो इलेक्ट्रिक फिटिंग का खर्च सरकार ने नहीं दिया है और यदि बिजली की फिटिंग पाठशाला में करवाते हैं तो बिजली का बिल कोई नहीं देता है। पाठशालाओं में टी.वी., रेडियो देते समय क्या सरकार ने इसके ऊपर विचार नहीं किया था कि बिजली कहां से आयेगी, बिजली का बिल कौन भरेगा? इन साधनों को रखने के लिए अलग वर्ग खण्ड की जरूरत पड़ेगी, क्या हम इसके बारे में भी नहीं सोच

सकते? स्कूलों में बिना सोचे रेडियो और टी.वी. दे दिया और अब वे बेकार हालत में स्कूलों के रूमों में पड़े हुये हैं।

मैडम, छोटे-छोटे बच्चे सुबह 11.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक पाठशालाओं में रहते हैं लेकिन पाठशालाओं में पेशाबघर, पायखाना नहीं हैं। बच्चे एक बार पाठशाला में आ गये तो पाठशाला के बाहर नहीं जा सकते हैं। मैडम, कपार्ट की योजना यूरिनल और टायलेट बनाने की है लेकिन अभी तक उस पर कार्य शुरू भी नहीं हुआ है। यूरिनल और पाखाना का हर पाठशाला में प्रबन्ध होना चाहिए। पाठशालाओं में शुद्ध पीने का पानी नहीं मिलता है। जब गांव में शुद्ध पीने का पानी नहीं है तो पाठशालाओं में शुद्ध पानी कहां से आयेगा? पाठशाला में मध्याह्न के समय भोजन की योजना चलाई है लेकिन भोजन के बाद पीने का पानी नहीं मिलता है और बच्चे पानी पीने के लिए घर पर जाते हैं और फिर वापस पाठशाला में नहीं आते हैं। इससे शिक्षा पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

इसके अलावा हर पाठशाला में ब्लैक बोर्ड, पुस्तकालय, बैंच, शिक्षकों के लिए कुर्सी, टेबल, पंखा, प्रार्थना के लिए माइक, बच्चों के लिए गेम्स के साधन, यूनिफार्म, घड़ियाल, घंटी, सरस्वती की मूर्ति और प्रार्थना के समय बच्चों के लिए चटाई जैसे कई चीजों की आवश्यकता होती है। आप सोचिये क्या ये सब चीजें स्कूलों में उपलब्ध हैं? बच्चों को भविष्य में हम भारत के सच्चे नागरिक बनाना चाहते हैं, राष्ट्रीयता के संस्कार देना चाहते हैं मानसिक, शारीरिक और सामयिक दृष्टि से बच्चों को स्वस्थ बनाना चाहते हैं तो पाठशालाओं में इसका वातावरण बनाना होगा। यह सोचने की बात है कि प्रार्थना बिना माइक के कैसे हो सकती है? अगर पाठशालाओं में अच्छी प्रवृत्ति नहीं होगी तो बच्चे कहां से अच्छे संस्कार प्राप्त कर सकेंगे?

प्राथमिक शालाओं में सुविधा कैसी है और कैसी होनी चाहिए, इस पर एक सर्वेक्षण हुआ है।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा) : आनन्दीबेन जी, एक मिनट के लिए मैं सदन की अनुमति लेना चाहूंगी क्योंकि मुझे वीमेन्स रिजर्वेशन बिल की ज्वांइट सिलेक्ट कमेटी में जाना है। सदन की अगर अनुमति हो तो माननीय सदस्य श्री सनातन बिसि को मैं चेयर पर बैठा दूं?

कुछ माननीय सदस्य : एग्रीड।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा) : थैंक्यू, सो मच।

(उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि) पीठासीन हुए)

श्रीमती आनन्दीबेन जेठाभाई पटेल : प्राथमिक स्कूलों में सुविधाएं कैसी होनी चाहियें और आज कैसी हैं, इसका एक सर्वेक्षण हुआ है। उसी सर्वेक्षण की रिपोर्ट मैं सदन के सामने रखना चाहती हूं। जब यह रिपोर्ट आपके समक्ष आई है तो इसे देखकर हमको प्राथमिक शिक्षा की दशा की अनुभूति होगी। सर्वेक्षण के अनुसार पूरे देश में 9 परसेंट स्कूल ऐसे हैं जिनके पास अपना कोई भवन नहीं है। ज्यादातर ऐसे स्कूल पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में हैं। इनमें से केवल 58.5 स्कूलों में ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था है अन्य स्कूलों में ब्लैक बोर्ड की भी व्यवस्था नहीं है। 72 परसेंट स्कूलों में पुस्तकालयों की सुविधा भी नहीं है। 70 परसेंट स्कूलों में पेशाबघर व शौचालय भी नहीं है। 49 परसेंट स्कूलों में पीने के पानी की सुविधा भी देना बाकी है। 30 परसेंट विद्यालयों के भवन अच्छे थे अन्य विद्यालयों के स्थान प्रदूषित वातावरण में, कोलाहलपूर्ण वातावरण में थे, वायु व प्रकाश की कमी थी, फर्नीचर पर्याप्त मात्रा में नहीं था। गांवों में समस्या अत्यन्त कठिन है। वहां अधिकतर स्कूल ऐसे हैं जहां दिन में पढ़ाई होती है और रात को प्रधान या सरपंच के बैल बांधे जाते हैं। विद्यालय मौसम की दया पर खुलते हैं या बन्द होते हैं। बारिश के मौसम में या सर्दी के मौसम में बन्द रहते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे बच्चे कैसी पढ़ाई कर सकते हैं, वह हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं।

आगे मेरा यह कहना है कि कई बालक-बालिकाएं स्कूल में भर्ती ही नहीं होते हैं, यदि भर्ती होते भी हैं तो बीच में ही शिक्षा को छोड़ देते हैं। सातवीं श्रेणी तक पढ़ने के बाद भी पढ़ना-लिखना आता ही नहीं है। बच्चों को पढ़ाई के समय कई कठिनाइयां आती हैं। इन कठिनाइयों का संबंध खासकर के ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों से है। राजस्थान जैसे रेतीले प्रदेश में शाला बहुत दूर होती है, कश्मीर, गढ़वाल और हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में शालाएं बहुत दूर होती हैं। असम, मध्यप्रदेश और दक्षिण भारत के घने वनों के क्षेत्रों में अल्प-संख्यक सुदूर गांवों में रहते हैं। इन सभी क्षेत्रों में यातायात के साधनों की कमी है, मार्ग सुरक्षित नहीं होते हैं, मौसम प्रतिकूल होता है। कभी अधिक वर्षा या ठंड होती है। अल्प संख्या वाले क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय न होने से माता-पिता अपने लाडले बच्चों को विद्यालयों में भेजते ही नहीं हैं। गरीब मां-बाप अपने बच्चों को विद्यालयों में नहीं भेजते हैं लेकिन कार्य करने के लिए भेजते हैं जिससे आर्थिक सहायता परिवार को मिले। बच्चे खेतों में मजदूरी करते हैं। जब तक उनके माता-पिता की गरीबी दूर नहीं होती तब तक हमारा अनिवार्य शिक्षा का सपना पूरा नहीं होगा, साकार नहीं होगा।

स्कूलों में फीस माफ है लेकिन फीस के अलावा पुस्तकें खरीदने में, नोट-बुक खरीदने में, पैंसिल खरीदने

में और यूनिफॉर्म बनाने में खर्चा तो होता ही है। जिस परिवार को खाने के लाले पड़ रहे हैं, ऐसे परिवार अपने बच्चों को शाला तक कैसे भेज सकते हैं। समाज में कई कुरीतियां फैली हुई हैं जिससे शिक्षा का प्रसार कम होता है जैसे कि बाल विवाह, जाति प्रथा, बालिकाओं की शिक्षा के प्रति उदासीनता, सहशिक्षा को बुरा मानना, अस्पृश्यता, धार्मिक दृष्टिकोण और रूढ़िवादी आदि। छोटी आयु में विवाह हो जाने से बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। कट्टर जातिवादी लोग अपने बच्चों को निम्न जाति के बच्चों के साथ पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं। बालिकाओं को घर-गृहस्थी करनी है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। विवाह हो जाने के बाद वह दूसरे घर चली जायेगी तो उसको पढ़ाने की क्या आवश्यकता है?

कई लोग रूढ़िवादी होने से बच्चों को स्कूल में ही नहीं भेजते हैं। कई माता-पिता अनपढ़ होने से शिक्षा का महत्व नहीं समझते। आज भी ऐसे परिवार हैं जहां महिलाओं को घरों की चार-दीवारी से बाहर कदम रखने की इजाजत नहीं है। तो ऐसी महिलायें और ऐसे परिवार अपने बच्चे-बच्चियों को स्कूल कैसे भेज सकते हैं? वे उनको भेजने के लिए मना करते हैं। हरिजन और आदिवासी महिलाओं के बीच अनपढ़ों की संख्या ज्यादा है। लगभग 95 प्रतिशत महिलायें इनके बीच निरक्षर हैं। भारत सरकार अभी तक अपना ध्यान प्राथमिक शिक्षा की तरफ केंद्रित नहीं कर सकी है। आजादी के बाद भारत सरकार किसी न किसी समस्या में उलझी हुई रही है। कश्मीर की समस्या, शरणार्थियों की समस्या, खाद्यान्न की समस्या, साम्प्रदायिक दंगा, मुद्रा अवमूल्यन, चीन और पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध से उत्पन्न समस्या, असम और पंजाब में आतंकवाद की समस्या, ऐसी कई समस्याओं को हल करने में सरकार व्यस्त रही और सरकार प्राथमिक शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दे पाई। हमारी शिक्षण पद्धति पुरानी हो गई है, रस-हीन हो गई है। गणित और विज्ञान पढ़ाने के लिए नये तरीके ढूंढने की बात भी अनदेखी की जा रही है। साथ ही साथ भाषा की समस्या भी है। एक ही क्षेत्र में अगल-अलग भाषा बोलने वाले बच्चे रहते हैं। ऐसे बच्चों के लिए अलग अलग विद्यालय शुरू नहीं किए जाते हैं। बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की संख्या 77 प्रतिशत है। पहली कक्षा में 100 बच्चे होते हैं तो आखिरी कक्षा तक 35 ही बच्चे पहुंच सकते हैं। प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन ज्यादा होने से प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य करने में कठिनाई आती है। लेकिन अगर सरकार चाहे तो इन कठिनाइयों का हल हो सकता है।

अब मैं सदन का ध्यान बालिका शिक्षा के बारे में आकर्षित करना चाहती हूं। हमारे लिए बालिकाओं की शिक्षा एक गंभीर विषय है। सरकार का रवैया बालिका शिक्षा की ओर सौतेली मां जैसा रहा है। बालिका-शिक्षा की सरकार ने कोई चिंता नहीं की। एक बालिका पढ़ेगी तो दो परिवारों को फायदा होगा। 1991 के आंकड़ों के हिसाब से 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सात करोड़ बच्चे स्कूल में गए ही नहीं है। 6 से 11 आयु वर्ग के बच्चों का यह आंकड़ा पांच करोड़ है। इसमें पौने तीन करोड़ बालिकायें हैं। प्राइमरी स्तर पर बालिकाओं का ड्राप आउट 65 से 70 प्रतिशत है और लड़कों का 30 प्रतिशत है। इतने बालक और बालिकायें बीच में से पढ़ाई छोड़ देते हैं। भारत में महिलाओं की संख्या कुल जनसंख्या का 50 प्रतिशत है। अगर उच्च शिक्षा की बात करें तो पुरुषों से तीन गुना ज्यादा महिलायें अनपढ़ है। देश में सात करोड़ पुरुष ऐसे हैं जो अनपढ़ हैं और 19 करोड़ 17 लाख महिलायें ऐसी हैं जो अनपढ़ हैं। विडम्बना तो देखिए कि एक ओर तो अनपढ़ महिलाओं की फौज है और दूसरी तरफ सरकार द्वारा महिलाओं के लिए रोजगार में आरक्षण की घोषणा की जा रही है। महिलाओं को राजनीति में 33 प्रतिशत आरक्षण देने की बात है। लेकिन ग्रामीण बालिकायें स्कूलों में भर्ती ही नहीं हो पातीं। ऐसा विरोधाभास देखने को मिल रहा है। जब हम इक्कीसवीं सदी में जाने की बात कर रहे हैं तब भी भारत में महिलाओं की स्थिति ऐसी ही है। ऐसे में बालिकाओं की स्थिति कैसे सुधरेगी?

घर के प्रवेश द्वार में प्रवेश करते समय आधा शरीर अंदर और आधा शरीर बाहर, ऐसी स्थिति महिलाओं की हो गई है। साक्षर पुरुष तो लाभ उठा पायेंगे अनपढ़ महिलायें इस लाभ से वंचित रह जायेंगी। महिलाओं की शिक्षा की चिंता सरकार को करनी होगी। बालिका शिक्षा पर सरकार और समाज का विशेष ध्यान देना होगा। बालिका शिक्षा के लिए मैं कुछ सुझाव देने जा रही हूं।

प्राथमिक स्कूलों के शिक्षको के बारे में मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। प्राइमरी स्कूलों में प्रशिक्षित शिक्षक 1950 में 58.8 थे, 1960 में यह बढ़कर 64.8 हुए, 1970 में 76.9 हुए और 1980 में 89.9 हुए। उपरोक्त आंकड़े बताते हैं कि प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या में वृद्धि हुई है। 1980 तक प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या 21.7 लाख थी लेकिन आज ऐसे शिक्षकों की संख्या 44 लाख है। इतनी ज्यादा बढ़ गई है। क्या योग्य व्यक्ति प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाना पसंद करेंगे? क्या हमारी राज्य सरकारें उनकी सेवा और वेतनों को सुधारने का प्रयत्न करेंगी? आज प्राथमिक शिक्षक उपेक्षित हैं। इन शिक्षकों का शोषण हो रहा है। ऐसी स्थिति में शिक्षक कैसे शिक्षण कार्य कर सकता है। शिक्षक पढ़ाता कम है और ट्यूशन ज्यादा करता है और उसके पास जो समय बचता है उसमें

वह राजनीति भी कर लेता है। ऐसी स्थिति में हम शिक्षकों से क्या अपेक्षा रखेंगे? महोदय, मैं आपको बताना चाहती हूं कि शिक्षक शिक्षण कार्य के अलावा क्या कार्य करता है और हमारी सरकार शिक्षकों से कैसे कार्य करवा रही है। महोदय, प्राथमिक शाला के शिक्षकों को शिक्षण कार्य के अलावा अन्य कई कामों में लगाया जाता है। जैसे कि चुनाव की ड्यूटी कराना, कुटुम्ब कल्याण के लिए पेशेंट लाना, गांवों में पशुओं की गिनती के लिए उन्हें भेजना, मलेरिया की गोलियां वितरित करना, पोलियो जैसे रोग के कार्यक्रम में भाग लेना, पौष्टिक आहार वितरित करना और एडल्ट एजूकेशन में भी शिक्षकों को लगाया जाता है। आप बतलाइए शिक्षक कब शाला में जाएगा और शिक्षण कार्य कब करेगा, अभ्यास कब करेगा? इसके लिए उसके पास समय ही नहीं है। शिक्षकों की बड़ी दयनीय स्थिति है। शिक्षकों से सरकार सभी काम करवा रही है। शिक्षकों की इच्छा के विरूद्ध सारे काम कराए जाते हैं। केन्द्र सरकार को इसे देखना चाहिए और शिक्षकों को इन कामों से मुक्त करवाकर उनसे सिर्फ बच्चों की पढ़ाई करवानी चाहिए। क्या केंद्र सरकार ऐसी इच्छा रखती है कि इस काम के लिए युवक-युवतियों को तैयार किया जाए? हमारे देश में ऐसे युवक लाखों की तादाद में हैं जो बेकार हैं। ऐसे युवकों को इन कामों में लगाना चाहिए।

सरकार की ओर से प्रति विद्यार्थी 4 रुपया ग्रांट मिलती है। यह 4 रुपया ग्रांट जो मिलती है इसमें से जो अधिकारी-गण वहां आते हैं उनके डी.ए. और टी.ए. में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसी में से उनके लिए निकालना पड़ता है। इसलिए यह ग्रांट पर्याप्त नहीं है। यह ग्रांट प्रति विद्यार्थी कम से कम 15 रुपया देने की आवश्यकता है।

सर, राज्यों में जो आश्रमशालायें हैं, उनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूं। कई राज्यों में बहुत तादाद में आदिवासी छात्र हैं। इन आदिवासी छात्रों के लिए आश्रमशालायें चलती हैं। लेकिन कई आश्रमशालायें सिर्फ कागज पर है। गुजरात में कई ऐसी आश्रमशालायें जो कागज पर थीं, उनको ढूंढकर बंद करवाया है और उन पर कानूनी कार्यवाही चल रही है।

लाखों रुपये ग्रांट के सरकार के बचे रहते हैं। आश्रमशालायें चलाने में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार हो रहा है खास करके बालिकाओं के लिए जो आश्रमशालायें चलती हैं उनमें बालिकाओं के शरीरिक उत्पीड़न और शरीरिक शोषण की शिकायतें पेपरों में आती रही हैं। सामाजिक संस्थाओं से भी आती रही हैं। आश्रमशालाओं के ट्रस्टी कैसे हीन कार्य बालिकाओं से करवाते हैं जब वह सुनते हैं तब सिर शर्म से झुक जाता है। मैं इस विषय में आपके समक्ष दो घटनाएं रखना चाहती हूं। मैं भी वहां पर गई थी और पूरी इन्क्वायरी की थी। दो साल पूर्व गुजरात में ऐसी दो शर्मनाक घटनाएं आदिवासी महिलाओं के साथ, बालिकाओं के साथ घटी। दोनों के केस अभी कोर्ट में चल रहे हैं। तीन बच्चियों को ज़हर पिला दी गई थी या उन्होंने ज़हर पी ली थी, यह तो कोर्ट तय करेगी लेकिन यह सच है कि ऐसी तीन बच्चियां जो प्राथमिक शाला में पढ़ती थीं वह बच्चियां ज़हर की वजह से खुदा को प्यारी हो गई थीं। 14 साल की एक बालिका ने मृत बच्चे को जन्म दिया था। यह केस भी कोर्ट में चल रहा है:। आश्रमशालाओं में शिक्षण कार्य चलता है या वैश्यावृत्ति चलतो है, यह मैं पूछना चाहती हूं ? शिक्षण कार्य आश्रमशालाओं में चलता है या वैश्यावृत्ति चलती है, यह प्रश्न आम समाज भी पूछ रहा है। अधिकारियों की सांठ-गांठ से इस प्रकार के ट्रस्टी छूट जाते हैं। सरकार की नीयत अच्छी है। स्कूल दूर होने के कारण, यातायात की सुविधा नहीं होने के कारण बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। ऐसे बालकों और बालिकाओं के लिए आश्रमशालायें शुरू की गई जहां अपने व्यवसाय के साथ-साथ पढ़ाई भी होती है। पढ़ाई का खर्च सरकार की ओर से दिया जाता है। बच्चे कम होते हैं लेकिन कागज़ों पर ज्यादा बच्चे दिखा कर सरकार की और से ग्रांट ले लेते हैं। आश्रमशालायें भ्रष्टाचार का साधन बन चुकी हैं। इसमें शिक्षकों की स्थिति भी गम्भीर है। वेतन बहुत कम मिलता है और उनका शोषण ज्यादा होता है। आश्रमशालायें चलाने का उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसी आश्रमशालाओं की जांच करने की आवश्कता है। करोड़ों रुपयों की ग्रांट सरकार बचा सकती है। जो आश्रमशालायें अच्छी चलती हैं उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिये, ज्यादा सुविधाएं दी जानी चाहिये। जो कागज़ी आश्रमशालायें हैं, ग्रांट ले कर हज़म कर जाते हैं, उनको हिम्मतपूर्वक बन्द कर देना चाहिये। सरकार से यह कदम उठाने के लिए मैं अनुरोध करती हूं। जहां उत्पीड़न और शोषण की शिकायतें मिलती है वहां जांच करवा कर दण्डित करना चाहिये।

उपसभाध्यक्ष महोदय, अब मैं आपका ध्यान प्राथमिक शालाओं में चलती मध्याह्न भोजन योजना की ओर दिलाना चाहती हूं। मध्याह्न भोजन योजना इसलिए शुरू की गई थी कि दलित और गरीब बच्चे आकर्षित हो कर शाला में आएं, शाला में बच्चों की संख्या बढ़े, अनिवार्य शिक्षा का हमारा उद्देश्य पूर्ण हो। दुनिया के अन्य देशों में भी बच्चों को भोजन देने की परम्परा है क्योंकि वहां शाला सुबह 8 बजे से शुरू होती है और शाम को 4 बजे तक चलती है। इसलिए बच्चों को लंच देने की जरूरत पड़ती है। भारत में

शालाओं का समय 11 बजे से पांच बजे तक होता है। बीच में लंच की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि हम चाहते हैं कि नाश्ता देना जरूरी बनता है तो इसके लिए बच्चों को फूड पेकेट देने चाहिये। इसके लिए हर राज्य में न्यूट्रिशन प्लांट शुरू करने चाहिये। शाला में अभ्यास के लिए पर्याप्त संख्या में वर्गखंड नहीं हैं तो मध्याह्न भोजन के लिए अलग वर्गखंड कहां से लाएंगे? भोजन वर्गखंड में ही बनता है जहां हमारे बच्चे पढ़ते हैं। पानी की व्यवस्था भी नहीं होती है। शिक्षक भोजन बनवाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, इसमें व्यस्त रहते हैं । रिसेस तक यह भोजन की प्रक्रिया चलती रहती है। कई बच्चे भोजन नहीं करते। ऐसे बच्चों को देरी से शाला में माता-पिता भेजते हैं क्योंकि दो बजे तक भोजन चलता रहता है। यह प्रथा बन्द कर के बच्चों को फूड पेकेट देने चाहिये।

ऐसा मेरा अनुरोध है। कई प्राथमिक शालाओं में बाल मंदिर भी चलता है। प्राथमिक शालाओं के बच्चे जब भोजन करते हैं तब बाल मंदिर के बच्चे टुकुर-टुकुर भोजन लेते हुए बच्चों की ओर देखते रहते हैं। क्योंकि सरकार प्राथमिक शाला में मध्याह्न भोजन योजना चलाती है, बाल मंदिर में नहीं चलाती है। बाल मंदिर के बच्चों को भोजन नहीं मिलता है। सिर्फ दूर से देखना ही उनके भाग्य में लिखा गया है। कैसी हमारी मध्याह्न भोजन योजना है? सब से छोटे बच्चे को न्युटीशन की जरूरत है लेकिन उसको नहीं मिलता है। सरकार यह देखती है। लेकिन संविधान के मुताबिक वचनबद्धता से ऐसे बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकती है। गुजरात में जब भा.ज.पा. की सरकार बनी तब मध्याह्न भोजन योजना में सुधार किया गया। बच्चे स्कूल में आते थे। प्रति बच्चे को दस किलो अनाज दिया जाता था। यदि एक परिवार के तीन बच्चे होते हैं और स्कूल में तीनों बच्चे आते है। तो 30 किलो अनाज दिया जाता था। तीस किलो अनाज में से बच्चों को तो रोटी मिलती थी, साथ में परिवार को भी इसमें से रोटी मिलती थी। स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ी थी। बच्चे नियमित रूप से स्कूल में आने लगे थे क्योंकि जो बच्चा मजदूरी पर जाकर कमाता था उतना ही उसको दस किलो अनाज यहां मिलता था। माता-पिता भी बच्चों को मजदूरी करने के लिए नहीं भेजते थे बल्कि शाला में भेजते थे। लेकिन आज जो मध्याह्न भोजन योजना चल रही है उसको बंद करके बच्चों को फूड पैकेट देने की आवश्यकता है। इससे भोजन पकाने का समय बचेगा। शिक्षक मुक्त हो जायेंगे और पढ़ायी भी अच्छी तरह से होगी।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा का विचार किया गया था। जो बच्चे शाला में दाखिल नहीं होते थे और बीच में ही अध्ययन छोड़ देते थे ऐसे बच्चों के लिए यह प्रबन्ध किया गया था। आंकड़ों के अनुसार 1982-83 तक 68 हजार से अधिक केन्द्र खोले गए। इनमें 14.7 लाख विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया। आशा की जाती है कि 3 करोड़ 90 लाख बच्चे इसी पद्धति से शिक्षा पायेंगे। लेकिन ऐसी आशा निराशा में बदल सकती है। बच्चे प्रभावी शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे। मूल्यांकन में कठिनाइयां आ रही हैं ऐसी शिक्षा को लोग निम्न स्तरीय मानते हैं। बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। देश भर में हरेक स्टेट में प्राइवेट प्राथमिक शालाएं भी चल रही हैं। प्राइवेट प्राथमिक शालाएं कैसे चल रही हैं उसका भी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। गुजरात सहित कई राज्यों में प्राइवेट प्राथमिक शालाएं शुरू हुई हैं। मोटे तौर पर ऐसी शालाएं शहरी क्षेत्रों में हैं। सरकार ग्रांट तो नहीं देती है। फीस से ऐसे स्कूलों का काम चलता है। वहां प्रवेश फ्री, प्रवास फ्री, सांस्कृतिक फ्री ट्यूशन ऐसी तरह-तरह की 6 महीने की फीस एक साथ ली जाती है प्रवेश तभी मिलता है जब डोनेशन दिया जाता है। ऐसे कई स्कूल हैं जो बिना डोनेशन प्रवेश ही नहीं देते हैं। यदि परिवार में दो-तीन बच्चे हैं तो 30 से 40 हजार डोनेशन परिवार कहां से लायेंगे? हर महीने फीस तो अलग होती है। अभी तो एक नया तरीका शुरू हुआ है कंप्यूटर सिखाने का और 6 माह की 400 रुपया फीस ली जाती है। पूरी कक्षा में 30 बच्चे या 50 बच्चे हैं तो सब को साथ में कंप्यूटर सिखाया जाता है और कंप्यूटर की संख्या 8 से 10 होती है। यह सीखना कंप्लसरी होता है। एक ओर मंहगाई बढ़ने से मध्यम वर्ग के आदमी को रोटी खाना मुश्किल है तो बच्चों की पढ़ाई का खर्च कहां से आएगा? प्राइवेट माध्यमिक शालाओं में शिक्षकों की स्थिति भी दयनीय है नियुक्ति के समय 50 हजार से एक लाख रुपये का डोनेशन लिया जाता है तब शिक्षक को नौकरी मिलती है। आप जानते हैं कि उसे सेलरी कितनी दी जाती है? चार सौ से पांच सौ रुपये सेलरी दी जाती है। शिक्षकों का शोषण होता ही रहता है। वर्ग खंड में 80 तक बच्चे होते हैं। बैठने की जगह भी नहीं होती है। ऐसी स्थिति में शिक्षक शिक्षण कार्य कैसे कर सकता है? शिक्षकों की मांग है कि हमें बैंक द्वारा सेलरी दी जानी चाहिए, लेकिन कोई ऐसा करना नहीं चाहता है। सरकार इस समस्या पर ध्यान नहीं देती है। बच्चों की जो फीस आती है, वह बैंक में इकट्ठी होनी चाहिए और उस में से शिक्षकों का वेतन और अन्य खर्च किया जाना चाहिए।

महोदय, हर साल स्कूलों की फीस बढ़ायी जाती है, लेकिन वेतन नहीं बढ़ता है। प्राइमरी स्कूल्स चलाकर मुनाफा कमाना एक व्यवसाय हो गया है। सुबह जिस

बिल्डिंग में सेकंडरी और हायर सेकंडरी स्कूल चलता है, उसी बिल्डिंग में दोपहर का प्राइवेट स्कूल्स चलते हैं। सेकंडरी और हायर सेकंडरी स्कूलों के लिए मकान का किराया ट्रस्टी को सरकार देती है। उसी मकान का किराया वही ट्रस्टी प्राइवेट स्कूल के प्रिंसीपल से लेकर भ्रष्टाचार भी करते रहते हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि) : मैडम, कंकलूड करिए।

श्रीमती आनन्दीबेन जेठाभाई पटेल: अन्य विकसित देशों की तुलना में भारत में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति निराशाजनक, दिशाहीन और दयनीय है। अब भी स्कूलों में पूर्ण सुविधाएं - प्रशिक्षित शिक्षकों की पर्याप्त संख्या, पाठ्य-पुस्तकों को ठीक से तैयार करना, पढ़ाई के विविध तरीके अपनाना, योग्य व्यक्तियों को प्राथमिक शिक्षा की ओर आकर्षित करना, शिक्षकों का शोषण व उपेक्षा से छुटकारा दिलाना, नौकरीशाही को भ्रष्टाचार की चंगुल से छुड़ाना और संवैधानिक वचनबद्धता की दृष्टि से शिक्षक, समाज, माता-पिता, निरीक्षकों और प्रबंधकों को जवाबदेह बनाने की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो देश में इतना तनाव होगा कि व्यवस्था बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा।

महोदय, इस के लिए मैं कुछ सुझाव सदन के सामने रखना चाहती हूं। गांधीजी की बुनियादी शिक्षा पर आधारित समाज उपयोगी उत्पादक-कार्य के कार्यक्रम को अपनाना होगा। शिक्षकों को देहाती क्षेत्रों मे जाने के लिए प्रेरित करना होगा। उन्हें ज्यादा वेतन देना होगा और वहां रहने के लिए आवास सुविधा भी उपलब्ध करानी पड़ेगी। शिक्षण संस्थाओं में आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था जैसे कम-से-कम दो बड़े कमरे हों, आवश्यक खिलौने, ब्लैक बोर्ड, मानचित्र, चार्ट तथा वैज्ञानिक उपकरण आदि पर्याप्त संख्या में प्रत्येक प्राथमिक शाला में होना आवश्यक है। प्रत्येक विद्यालय में कम-से कम दो शिक्षक हों जिन में एक महिला हो। एक शिक्षक एक कक्षा के आधार पर शिक्षकों का प्रबंध होना चाहिए और जल्द ही होना चाहिए। बीच में स्कूल छोड़नेवाले बच्चों, जहां कोई प्राथमिक स्कूल नहीं है वहां के बच्चों तथा जो बच्चे कार्यरत होने से स्कूल नहीं जा सकते, उन सब बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा का प्रबंध क्रमबद्ध होना चाहिए। मोबाइल हॉस्पीटल और मोबाइल लायब्रेरी की तरह मोबाइल स्कूल्स की व्यवस्था भी ऐसे बच्चों के लिए कर सकते हैं। शिक्षा बाल केन्द्रित तथा क्रिया आधारित बनानी चाहिए। शारीरिक दण्ड नहीं दिया जाना चाहिए तथा बच्चों की सुविधा के आधार पर छुट्टियों का भी प्रबंध करना होगा। किसी बच्चे को एक ही वर्ग में नहीं रोका जाना चाहिए। हर जिले में एक प्रशिक्षित संस्था होनी चाहिए जोकि शिक्षकों की सेवा-पूर्व तथा सेवा दरमियान शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था करे। अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था स्वैच्छिक संस्थाओं एवं पंचायती राज की संस्थाओं द्वारा की जाए और सरकार की ओर से पर्याप्त मात्रा में धन सही समय पर दिया जाना चाहिए। प्रत्येक राज्य अपने कुल राजस्व का दस प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा पर व्यय करे और इतनी ही मात्रा में केन्द्र सरकार व्यय करे। विद्यालय भवनों का पूरा उपयोग करने के लिए दोहरी पाली में विद्यालय चलाए जाएं। शिक्षा के लिए दिए जाने वाले दान की राशि को आयकर राशि से मुक्त किया जाना चाहिए। राज्य सरकारों को स्वायत्त प्राथमिक शिक्षा परिषदों का गठन करना चाहिए और उसे शिक्षा का विकास, अनुदान, पाठ्य-पुस्तकों के मूल्यांकन, शिक्षकों के प्रशिक्षण, शिक्षकों की नियुक्ति जैसे कार्य सौंपने चाहिए। बालिकाओं के लिए अलग प्राथमिक विद्यालय शुरू किए जाने चाहिए। मिल, कारखाने और बड़ी-बड़ी कंपनियों में बच्चे काम करते हैं और काम करना उन के परिवार को जरूर भी लगता है। ऐसी कंपनियों में बच्चों को पढ़ाने की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। मिल, कंपनियों और कारखानों पर दबाव डालकर प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करायी जानी चाहिए क्योंकि बच्चे काम करते हैं तो परिवार खा सकते हैं और काम छुड़वा देंगे तो परिवार भूखों मर जाएगा। कई परिवारों का अपना परंपरागत व्यवसाय होता है। अपना परंपरागत व्यवसाय सीखने के साथ साथ उनके बच्चों की पढ़ाई का भी प्रबंध होना चाहिए। स्कूल में परंपरागत व्यवसाय को बढ़ावा मिले। ऐसी प्रवृत्ति या ऐसा उत्पादक-श्रम शुरू करना चाहिए। दलित झोपड़-पट्टी में रहने वाले परिवारों को उसकी ओर जागरूक करना चाहिए ताकि वे अपने बच्चों को शाला में भेजें।

महोदय, चाइल्ड लेबर एक्शन नेटवर्क नामक एक गैर-सरकारी संगठन ने जो इस संबंध में सुझाव दिए हैं, वह सुझाव मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। चाइल्ड लेबर एक्शन नेटवर्क नामक गैर-सरकारी संगठन ने एक कार्यशाला का आयोजन किया था। उस कार्यशाला का विषय था - "अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा हेतु सामाजिक समर्थन"। तीन दिन की इस कार्यशाला में देश के 110 गैर-सरकारी संगठनों ने हिस्सा लिया। इस संगठन ने सरकार के सामने कई सुझाव रखे हैं, जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। संगठन का मानना है कि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का लागू करने के लिए समयबद्ध योजना की आवश्यकता है। पांच वर्ष की अवधि के भीतर प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य करें। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, जैसे

कि यूनिसेफ, यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को भी अपील करना चाहिए कि वे इस कार्यक्रम में भारत सरकार की मदद करें। प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए राजनैतिक इच्छा-शक्ति की जरूरत है। भारत के राजनेता नहीं चाहते कि यहां की जनता साक्षर हो। इसलिए राजनेताओं पर सामाजिक दबाव लाना चाहिए। हरेक राजकीय पार्टी में महिला शाखा, अनुसूचित/अनुसूचित जनजाति शाखा होती है, उसी तरह अनिवार्य शिक्षा शाखा खोलें।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Madam, you kindly conlcude. You have spoken very nicely. The last point is the main and important point. Madam, you kindly conclude.

श्रीमती आनन्दीबेन जेठाभाई पटेल: सर, पांच मिनट में मैं खतम करूंगी।

ऐसी शाखाओं में कार्यकर्ताओं को प्राथमिक शिक्षा का महत्व बताया जाए। ऐसी शाखा की अध्यक्ष महिला होनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा के संदेश को घर घर पहुंचाना जरूरी है। इसमें उद्योगपतियों, वकीलों, डॉक्टरों, अध्यापकों, ट्रेड यूनियनों और महिला संगठनों को भी जोड़ना चाहिए। सब बच्चे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर सकें, उसके लिए पर्याप्त धन होना चाहिए। नवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए जितना धन आवंटित किया जाता है, इसमें से 50 परसेंट धन प्राथमिक शिक्षा के लिए होना चाहिए। सरकार बालिका प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु बालिका शिक्षा बॉण्ड जारी करे। इस योजना के अंतर्गत जो माता-पिता अपनी बच्चियों को पहली कक्षा में दाखिल करें, उन्हें 500/- रुपए का बॉण्ड दिया जाए। इस बॉण्ड के बदले लड़की की आयु 18 वर्ष पूरी होने पर 20,000/- रुपए दिए जाएं। यह लड़की को अपना भविष्य सुधारने हेतु 20,000/- रुपए की राशि मिलेगी, लेकिन यह तभी भुगतान होगी, जब इस लड़की ने अपनी प्राथमिक शिक्षा नियमित रूप से पूरी की हो। इस योजना को एक साल में लागू करना चाहिए। बालिका शिक्षा बॉण्ड का सबसे ज्यादा लाभ दलित की लड़कियों और मुस्लिम वर्ग की लड़कियों को होगा। चीन, जापान, जर्मनी जैसे देशों में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य है। माता-पिता अगर अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते तो सरकार कानूनन कार्यवाही करती है। भारत सरकार को भी इस विषय में सख्ती करनी चाहिए। स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ-साथ देश में नए स्कूल बनाने, प्रशिक्षित अध्यापक नियुक्त करने, अच्छी किताबें और उसके उपकरण की सुविधा पर जोर देना चाहिए। देश के बजट का 6 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करना चाहिए और उसमें से 50 परसेंट इस बजट का प्राथमिक शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा सभी बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य करने के लिए जरूरी है कि तमाम राजनैतिक पार्टियां अपने मतभेद छोड़कर शिक्षा में बदलाव लाने के विचार विमर्श करें।

महोदय, यह एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें कोई मतभेद नहीं होगा। राष्ट्रीय सहमति से शिक्षा के लिए बजट का 6 परसेंट हिस्सा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अगर संयुक्त मोर्चा की सरकार ऐसा साहसिक कदम उठाएगी तो विरोधी पार्टियों का भी उसे समर्थन मिलेगा। शिक्षा के मामले में राजनैतिक हित अलग नहीं हो सकता। सभी पार्टियां चाहती हैं कि प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य हो, ठीक ढंग से चले पर्याप्त सुविधा हों, एक वर्ग एक शिक्षक हो। लेकिन, वर्तमान सरकार का राजनैतिक और सामाजिक चरित्र देखें तो संभव नहीं लगता कि इस सदी के अन्त तक वह प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना सके।

देवेगौड़ा सरकार की प्राथमिकता में प्राथमिक शिक्षा नहीं है, उन्हें तो अपने मोर्चे की 13 पार्टियों को और उनके नेताओं को संतुष्ट करने में ही आधी शक्ति खर्च करनी पड़ती है। मुझे संदेह है कि प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में यह सरकार कोई नया कदम उठा पाएगी। धन्यवाद।

The question was proposed.

PROF. NAUNIHAL SINGH (UTTAR PRADESH): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support the Resolution moved by Shrimati Anandiben Jethabhai Patel on the status of primary education in India. Primary education actually is a very important part of our life. It forms the basic foundation of our democracy and it is a root for our progress. But shockingly primary education in India is in a very woeful state. According to the Ministry of Human Resource Development, nearly 96 per cent of the children in the age group of 11—14 are enrolled in primary schools in India. However, it is construed that this number is about 30 to 40 per cent higher than the actual position. It is found that out of 100 pupils who join primary schools, 30 to 40 per cent of them reach Class-V and barely one-fourth of such students reach Class-VIII. This high drop rate in primary schools is the most disturbing feature of our programme of elementary education. This is quite rightly attributed to the poverty of the rural masses because the dropouts help their

families in odd jobs like cattle rearing, gathering fuel and dung for their families or acting as baby sitters when mothers are outside or are busy in some work.

[Vice Chairman (Shri Ram Deo Bhandari) *in the Chair.]*

It is no secret that many rural schools have no regular or trained teachers for long periods and about 25 per cent of them are just single-teacher outfits. I would like to make it clear that in several schools in the outlying North Western Zone, the teacher-pupil ratio is 1:100 as against 1:30 as recommended by the Government. Children sit on *tat patties,* which are neither washed nor replaced for years. Textbooks or lessons are lacking in authenticity. Recently in an interview, some publishers said that these books were written by people who have never visited those areas or those States. Besides, the educational planners, administrators and teachers are grossly neglecting the practical or effective communication dimension of the learning system. It has been seen that while students are taught to ensure cleanliness of their surroundings, the school premises especially toilets are very badly maintained. Likewise, while pupils are told about the grave risks associated with smoking and tobacco chewing, several members of school's staff and some teachers too are seen smoking and chewing pans.

By 2000 AD, India will have the largest number of graduates and the largest number of illiterates in Uie world. For every 10 million illiterates in the world, five million are Indians, that is, 50 per cent of the worlds illiterates. It is hard to beat the complexity of a society that boasts of a 500-year old intellectual tradition and harbours nearly 500 million illiterates. Of every 10 illiterates in India, seven are women. In other words, the national average in female literacy is a dismal 30 per cent. But it gets worse when you look at the least advantaged groups like the tribals. Primary schools are the foundations of any educational system. In India, as many as 44 per cent of primary schools do not have *pucca* buildings; six out of every 10 schools have two or less teachers; over 50 per cent have no facilities for drinking water; two-thirds of these schools lack playgrounds and 85 per cent have no toilets. The NCERTs fourth all-India educational survey showed that three were 1,297 primary schools in the country without a single teacher. Over 600 of these were in UP. In the so-called rich states like Maharashtra, things are not too different. What is happening? What accounts for the collapse of primary education in India? It would be unfair to attribute it to the cynicism among students. What about the attitudes of those who have run this country for over four decades? Article 45 of the constitution of India says: "The State shall endeavour to provide within a period of 10 years from the commencement of this Constitution, for a free and compulsory education for all children until they complete the age of 14 years." How honest to that directive principle successive Indian Governments have been can be judged from the fact that today over 50 million children are altogether outside the schooling system. Different State Governments are looking for ways to steadily privatise education through the backdoor. As the State backs out of the scene, even the few avenues open to the poor to educate themselves will disappear. Expenditure on education in India has been steadily falling in real terms and in erms of actual expenditure. It is nothing but a historic betrayal. Education was a major concern of the leaders of the Indian freedom struggle. The Congress National Planning Committee suggested in 1938 that education be given a minimum of 10 per cent share of the total outlay. In 1994 came the Gandhi Plan which again recommended that a statutory minimum of 10 per cent of the total plan outlay be reserved exclusively for education. What actually happened? With almost each successive Five Year Plan, the percentage allocated to education kept shrinking. The First Five Year Plan saw 7.22 pe cent of the total outlay going to education.

The Second Five Year Plan saw 6.2 per cent. By the Fourth Plan, this had fallen to 5.2 per cent The Fifth Plan saw thigs dip to 3.3 per cent. The Seventh Plan got 3.9 per cent of the total Plan outlay. Remember that these are, in a sense, theoritical figures. The amount allocated is not the amount actually spent. In the Seventh Plan, for example, education got 3.9 per cent of the total outlay, while the

amount actually spent came to only 3.6 per cent. During the First Plan period, the money on elementary education accounted for 55 per cent of all the money spent on education as a whole.

By the Seventh Plan, this share had fallen by over 20 per cent. In the Seventh Plan, the share of elementary education in the overail investment in education came down to 34 per cent. The simple truth is that succssive Governments of India have not had the slightest intention of honouring their constitutional obligation, their historic promise to the Indian people. They have been eroding the right of the people to education and they know it. Exactly a decade later, our education system remained what it was — a curate's egg, good only in parts and, therefore, no good on the whole. With a foundation like this, the mass literacy and national transformation remains a pipe-dream. Will the political leaders and the new parliamentarians rise above petty politicking and assorted chicanery and endeavour with honesty and despatch to ensure free and proper education to every Indian child? If implementation is carried out, it will affect positively other social problems that remain even 50 years after independence like population growth, health, womens' development, child labour and unemployment. In fact, the greatest failure of independent India has been its inability to educate all. Had we paid sufficient attention to elementary education after independence, we would have achieved mass literacy long ago, as well as laid a solid educational base for all-round progress, and thus most of the problems we face today, including the retrograde business of reservations and the pervert politics of divisiveness which have spawned, would not have been there. It is obvious, however, that a mere constitutional directive was not enough to make our Governments to do the right thing at the right time. Taking the required action on the educational front called for a sense for the future, political will and honesty of purpose. Instead, what we have had throughout is a dismal catalogue of basic unconcern, short-sightedness, all kinds of gimmickry, misconceived experimentation, plenty of periodical rhetoric and altogether perverse priorities and, consequently, a wobbly inverted pyramid passing for an education system. Thank you.

SHRI SANATAN BISI (ORISSA): As far as Article 45 of the Constitution is concerned, it is the obligation of the country and the citizens at large that we must ensure the compulsory primary education. As far as our constitution is concerned, I humbly submit that whenever we are taking oath on the floor of the Parliament/Assembly and when other persons are taking oath in various places, they make solemn affirmation to protect the Constitution, to safeguard the Constitution and to see that whatever terms are laid down by the Constitution are followed.

With utmost regret, I submit that we are not following the Constitution. Out of all the directives listed in the Directive Principles of State Policy, it is the only directive for which ihe Constitution has fixed a time-limit for implementation. And we have violated it. The second thing is, how far can we allow the State to flout this directive by saying that it is endeavouring to implement it? We are committing a crime in the name of the Constitution. Till now we have not been able to achieve what has been stated in the Directive Principles of State Policy.

With profound joy, I would like to submit that under the leadership of Shri P.A. Sangma, the hon. Speaker of Lok Sabha, a delegation comprising the Members of Lok Sabha and Rajya Sabha including the hon. Deputy Chairman, Shrimati Najma Heptulla including myself visited China to participate in the 96th Inter-Parliamentary conference which was held in Beijing from 16th September, 96 to 21st September, 1996. The Conference in which parliamentarians from 134 countries participated gave a clarion call for promoting greater respect for protection of human rights in general and for women and children in particular. I am not going through the details of the Conference and various resolutions that it adopted. I would like to draw the attention of this House and, through this House, the attention of the people of the whole country to some of the every relevant resolutions adopted by the Beijing Conference and I am doing this to promote awareness in the people of this country. Resolution No. 14 clearly states that

the number of economically exploited children has increased substantially over the last five years and that their working conditions have seriously deteriorated resulting in greater physical, emotional and mental suffering. Resolution No. 15. conscious that the causes of child labour are primarily rooted in poverty created by socio-economic inequalities as well as insufficient educational facilities.

So far as the present Resolution which we are discussing now is concerned, with resolution No. 16 it urges the national Parliament and the Government to ensure provision of compulsory primary education and health-care which should be accessible to all and be relevant to the individual child, paying particular attention to the inclusion of girls and children from the marginalised groups. The time has come that when we take our oath, we should at the same time ensure that whatever that has been stated in the Constitution, whatever resolutions that the Beijing Conference adopted are implemented as early as possible. I would request the concerned hon. Minister to come forward with daring steps. He should see that it is made compulsory during his tenure itself.

With these words, I conclude my speech.

Thank you, Mr. Vice-chairman.

SHRI RAMACHANDRAN PILLAI (KERALA): Mr. Vice-Chairman, Sir, I congratulate the mover of this Resolution for bringing forward this important issue for discussion before this House. Actually, the very existence and development of any country depend upon the content and form of education that it has. I remember a discussion that took place in the middle of 50's on this issue, particularly in the United States of America. It was immediately after the Soviet Union had sent a Sputnik into the outer space. The Americans were worried. They got despirited. They started asking-What is it that Johny does not know which Michael knows? The term 'Johny' is a common American name and the term 'Michael' is a common Russian name. They started discussing about the standard of education inAmerica.They started probing into why the Russians were able to do this and why the Americans failed to do this. In that discussion, all educationalists took part All politicians took part in it. Administration also took part in it. Ultimately, they identified some of the infirmities existing in their educational system. Through this example, I want to bring to the notice of this House the importance of education, the importance of the content of education and the importance of the form of education.

How are we educating the people? Of course, I always feel that there is a sort of hypocrisy existing in our system. We have written many, many great things in our Constitution. We speak many, many lofty things. But we fail to implement them and we don't show the sincerity in implementing those things. We don't also feel guilty as to why we failed to implement these things. I do not want to go into the details. But we have to approach this question of education in the light of the overall changes that are taking place in our country. The last Government, the previous Government initiated a new set of economic policies. What was the main thrust of the new economic policies initiated in the beginning of '90s? The Government is giving up everything. The Government is giving up its responsibilities. The Government is giving up its responsibilities. The Government as giving up the responsibilities for increasing productivity and production in agriculture. The Government is giving up its responsibility of irrigating the land, to expand the irrigated land. The Government has given up its responsibility for giving electricity to the people. The Government has given up its responsibility of running the public sector undertakings. The Government has reduced its allocation for education. Allocation for public health has been reduced. So, the Government has given up its responsibility. This new set of policies initiated by the previous Government have created a very, very difficult situation in our country. Their whole idea was, if the Government runs all these things, then that will lead to inefficiency, that will lead to waste. So, the Government has given up all these things and the Government has entrusted this task to the capitalist market. They have propagated a new theory in the country that this capitalist market can do wonders in this country, they can bring efficiency in this country, they can increase the productivity and production in agriculture, they can increase productivity and production in

industry, they can educate the pople in a better way, they can give medical facilities in a better way than the Government can. But we are happy that they have not given up this administration and Government to the market forces. These are the sort of policies that they have initiated in the beginning of '90s.

This has created a very serious situation in the entire education system. Actually, what is happening in the entire education system is that there is a deliberate attempt to sabotage the general education in this country. General education means education to educate the common people through the general stream—Government schools and controlled private schools. That general stream is being sabotaged because the Government is not allocating sufficient funds, the Government is not maintaining the schools, the Government is not giving maintenance grants to the schools, the Government is not filling up the vacancies and, if you look at it, there is a substantial decline in the entire allocation during this period. And, on the other hand, a deliberate attempt is also there to bring in a parallel system. There you have to pay more fees. There you get better education. So, actually the common people, the poorer sections are making use of the general system and the richer, the elite, are using the parallel system. So, by sabotaging the general education system, the Government is trying to strengthen this parallel system, the system that caters to the needs of the elite class. So, because of these policies the poorer sections who constitute an overwhelming majority in this country, are suffering.

They are getting sub-standard education and the richer sections who have enough resources are getting better types of education. So, they are getting opportunity in the society for reaping the benefits and they are exploiting others also. Therefore, I urge upon the Government to have a thorough review of the Education Policy which has become absolutely necessary in the context of previous Government's five years' rule. The Government should apply its mind and also make a thorough change in the Education Policy. It should be based on the needs of the overwhelming majority of this country. The overwhelming majority, as we all know, is the poorer sections, the common people. Based on that, you try to restructure the entire educational system. Otherwise, the poorer sections, the overwhelming majority's sufferings will be more. So, this is an important aspect and the Government should come forward for strengthening the general education system. It should give more allocation and also try to improve the contents of education. I don't want to go into that particular aspect because a lot of deficiencies and infirmities are there. So, I urge upon the Government to look into all these aspects and come forward with a new set of policies that cater to the needs of the country and that helps in the development and progress of the country. With these words, I conclude.

SHRI R. MARGABANDU (Tamil Nadu): Mr Vice-Chairman, Sir, I would like to share some of my thoughts regarding compulsory education for the children up to the age of 14 years. Sir, education is a base for decent and dignified life of a man, but it is lacking in about 60 per cent people of our country. A provision has been made in the Constitution that there will be free and compulsory education for all the children up to the age of 14 years. Though our Constitution was framed about 50 years back, still there is illiteracy in a large part of the country. No effort has been made in the right direction to see that education is given compulsorily to all the children. Why? What is the reason for that? The importance of education has not been given serious thought either by parents, or by schools and or by the Government. All of them have taken it lightly. The parents feel that it is not their responsibility, school authorities feel that it is not their responsibility and ultimately the Government feels that it is not their responsibility. So, all of them are shirking their responsibilities and it has resulted into this situation. Sir, there is no law on the land which compels parents, school authorities and the Government to provide compulsory education to all the children. There is no law which asks the Government to create infrastructure for providing free and compulsory education to all the children.

Sir, there should be a law, there should be a compulsion which makes even the parents feel that they will be penalised if they do not send

their'children to schools. Sir, for smallpox vaccination there is a law and if any person fails to get his children vaccinated, he is to be prosecuted in a court of law. But, here if a person does not send his children to school, there is no law to punish him. Unless there is a law for sending the children to school, the goal of compulsory education cannot be fulfilled and achieved.

Sir, there are two types of schools in India—Government schools and private schools. The standard of education in the Government schools is not very high because of the qualitative aspect of the teachers concerned. They have several other activities, apart from the teaching profession. As a result of this, education in the Government schools is not taken seriously. The students who come out from the Government colleges or other Government institutions are not able to compete with the others in the competitive examinations of State Public Service Commissions or the Union Public Service Commission. On the other hand, the private institutions are giving very good education and coaching. They are preparing the students and equipping them well to compete in the competitive examinations. So the Government should come forward with some stringent provisions, as far as teaching staff and teaching management are concerned. If a student does not attend the school, the school authorities simply send him out. I think this job should not end here. If a student absents himself from his school or college, investigation should be made by the school authorities as to why the student is not attending the school. If that student is not attending school for various reasons or certain circumstances are compelling his parents to divert him to some other work, then they should be made responsible. Unless such stringent action is taken and responsibility is fixed on the school authorities, I think, education will be taken in a very light way. There are two other things also which are responsible for this, namely, poverty and ignorance. These are the two factors which are coming in the way of compulsory education. Sir, I can say that the people who are below the poverty line divert their children to other jobs like *beedi* rolling, tanneries, match industry, etc. in order to augment their source of livelihood. For all these things, the children are being diverted so that they can earn something to augment the income of their families. Therefore, the families which are below the poverty.line should be given some incentives. As a mater of fact, it has been suggested that if these people are sending their children to schools, they should be given scholarships and certain other facilities in the schools.

Sir, I am proud to say that in ourTamil Nadu the late Shri Kamaraj has introduced a system that all children must be sent to school and children must be given the compulsory education. Thereafter, my leader, Dr. MGR, had experienced poverty in his younger days, in his life, and because of the poverty and because of the hunger he could not attend school and college. He introduced a scheme called 'mid-day meal scheme' where nutritious meal was given to all the school-going children. And then school uniform was given to the children so as to see that there should not be any inferiority or superiority complex in the minds of young children. Sir, I was appointed as Managing Director of the Text-Book Boad of Tamil Nadu. At the time nearly Rs. 80 crores were given to that organisation. I was administering that Board for one year. Sir, eighty crores were granted every year to that Board. The Board takes care of providing books, text-books, slates and all other materials which are required for a student. Free bus passes were given to students to travel in Government buses. Chappals were given to the children so that they should not feel the heat under their feet. These are the ameliorative measures that have been taken in Tamil Nadu. But, in spite of that still illiteracy prevails there. We can set things right only either through legislation or by compelling the parents to send their children to school. So long as it is optional, so long as it is at their whims and fancies that they send their children to school, I think, we will not fulfil the dreams of our Constitution that compulsory education should be given to all children.

Sir, just some time ago, we had been to Rajasthan where there is a scheme of non-formal education. There, the children were brought to school for a two-hour study. We

inquired why there was a non-formal education, why the small children were being brought during late hours. We were informed that the children were engaged in some avocation in their houses or somewhere and they earned something for their family and during leisure time they came to school. This is what non-formal education means, they said. When there is an Act in force, restricting child labour, how on earth, can the authorities who are given the responsibility to prevent child labour, allow these children to do odd jobs? I strongly appeal that the law should be strictly enforced for stopping child labour and bonded labour of children. Parents sell or pledge their children to some agencies for getting some annual return and sometimes children are sent to do the house-hold work and other things for getting a paltry sum of Rs. 100 or 500. Due to this the entire career of the child will be spoiled and who is going to give a guarantee for the child's future? Child labour, bonded labour and sale or pledge of children by their parents are responsible for that. Hence, I appeal to this august body that there should be an agency — either police force or some other independent agency — to investigate and find out the causes for this. And such children must be relieved from the bonded labour. Unless such kind of agency is there, I think the welfare of the children will be jeoparadised and there will be no education for them.

At the same time, I want to ask, what is the guarantee of employment even after getting education? People, who are graduates and post-graduates, are wandering in the streets for want of employment. They have no employment at all. Even after their post-graduation the Government is not ensuring employment for them. Say, a father has four sons and he has educated his first son up to the post-graduate level. But even up to the age of 35, which is the upper limit beyon'd which one is barred entry into Government service, that boy does not get a chance for employment. So what irks the parents is that even after educating their first boy up to post-graduate level he is jobless and naturally they feel that there is no use of sending the remaining children to school. That is the feeling that emanates from the parents. So such feelings have got to be removed and thereforece the Government must find a way to give some employment guarantee to educated persons so that a person is able to live on his own after getting education. So, even after graduation or post-graduation if a person is dependent upon his parents for his livelihood, naturally, the kind of importance that has to be given to education would be lacking, Therefore, Sir, I have to say that these are the several factors that have to be taken into/consideration, and I appeal to the Government, through you, that the Government must come forward to see that some employment is given to persons after they are educated.

Sir, 1 charge the Government that it is only the. Government which is responsible for the illiteracy in the country. The Government builds infrastructures for education, studies and other things but, still, after getting education there is no guarantee of employment for the educated people. That is why people are reluctant to go to schools and colleges in spite of all the provisions made by the Government. Unless employment guarantee is given to students after the completion of their studies, I feel that it will be very difficult to enforce compulsory education. But, at the same time, education is a fundamental right and the Government must see that education is given to every-body and those who refuse to get educated must be penalised. It is by this way alone that education can be made compulsory. With these few words, Sir, I conclude my speech.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAM DEO BHANDARI): Shri Jalaludin Ansari. ... Not presnet. Shri saifuddin Soz.... Not present. Dr. Y. Radhaikrishna Murty.

DR Y. RADHAKRISHNA MURTY (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, first of all I compliment the hon. Member for bringing forward this Resolution, and I am sorry that she is not here to receive my compliments. On an occasion like this, some sort of repetition and reiteration is inevitable. So, Sir, you will please excuse me if I indulge in some sort of repetition, though from a slightly different angle.

Sir, our Constitution has got Directive Principles, a multitude of them, and the most

important, probably, is on elementary education, and the most neglected also is the same. They are all clubbed together-anti-cow slaughter, prohibition, etc. -but they are all taken up by some of the State Governments. But, unfortunately, this particular aspect has been neglected.

Another important Directive Principle that has been neglected along with this is equitable distribution of the implements of production. So these two things, which are most important for the development of any country, have unfortunately been neglected for the last 50 years. And we are experts at forming commissions. Commissions after commissions were formed - any number of them. We are experts not only in setting up Commissions; we are equally experts at shelving the reports of these commissions.

The most important and the prestigious commission that was formed was the Kothari Commission. It gave a very detailed report on education, in general, and primary education, in particular. The very first sentence in the report of the Kothari Commission says that the future of India is made in the classrooms. But today, even after about twenty-five years of receiving that report, we do not have sufficient number of classrooms, sufficient number of schools and sufficient number of staff. As has been pointed out by another hon. Member, there are thousands and thousands of single-teacher schools in the country even today. When even that single teacher does not come, it is a holiday for the whole school; and this happens quite often.

Sir, we do not have buildings. We do not have blackboards. We do not have chalkpieces. That is why the scheme 'Operation Blackboard' came into being. That too with British aid. But even after the 'Operation Blackboard', the position, today, in some of the States is not much different than what it was before.

The point is: more than half the children in the rural areas and more than two-thirds of the children in the urban *ghettos* are not in school. They do not have the mind to go to school. They do not have the time to go to school. They have to work hard from the early age of six as bread-earners for their poor family. Unless that situation is corrected, I think only amount of pressure, either on the parents or on the children, would not work, as far as compulsory elementary education is concerned.

We have had many statements, very pious statements. The National Education Policy was there. It had openly admitted that there was deficiency in the education system; particularly, at the lower level. But matters did not improve after that Then, the Janata Dal Government constituted another committee, called the Ramamurti Committee. It also gave its report. But again, matters did not improve.

Then, the National Literacy Mission was launched sometime back, a few years back. It took up a scheme with all seriousness and, probably, with a novel idea—the then Chairman of the Mission was very enthusiastic about it; but later on, the enthusiasm died down when he left-of involving the voluntary organisations; particularly, the Bharat Gyan Vigyan Samiti was involved. It was a great success in some parts of the country; in some districts, specially, in Kerala; and one district in West Bengal. But the enthusiasm died down soon. Voluntarism has been discouraged somehow or other by the bureaucracy. The bureaucratic procedures did not encourage voluntarism. Therefore, the whole scheme evaporated. Probably, on paper, some results are there from the operation of the National Literacy Mission. But when you go to the field, when you see the post-literacy programmes and all that, you find the picture is most distressing in the villages.

Sir, many reports of the UN. organisation and other world organisations have pointed out about the importance of education in the development of a society or of a nation. Actually, they consider it as a precondition for the development of any society, for the development-of any nation.

Now, what do we do in the present condition? What we need, I think, is a strong political will, which is badly lacking in Government after Government. I think, in the present class dispensation, the ruling classes, as one great man has pointed out, "have a vested interest in perpetuating illiteracy" in the country. The near empty House, today, on this discussion is, probably, a proof of that

The economic status of the poor should be improved if we want to see their children in schools. The mid-day-meal programme is only a marginal encouragement or incentive: it is not the total answer to the problem.

The budget allocation on education should improve. As the hon. elder Member pointed out, it never exceeded 3 or 3.6 per cent of our budget. The ex-Prime Minister pointed out in some election meeting that hereafter it would be 6 per cent. I do not know whether the present Government respects that statement or it will be taken as another proverbial election promise.

The conditionalities of the Brettonwoods sisters are hanging on our heads. The economic reforms which we have been following in the last few years almost tell us this thing. At least one of the important conditions put on us is to spend less and less on social services. Health and education form very important social services in our country.

The second is encouraging privatisation both in the educational field and the health sector. Therefore, it is not surprising that for the last few years we are seeing mushrooming of the elitist private schools. We see magnificent buildings of some of them. Some private schools are located in small residential houses, dingy residential houses, but they are doing fine.

But one thing I always find is that the staff in our Government schools are better equipped intellectually and educationally than most of the staff in private schools. I have had the first-hand experience of most of the private schools. They get staff at a very paltry sum. Unemployment is very rampant in our country. They are getting teachers even at Rs.200/- or Rs.300/-. At this paltry amount they get teachers, most of whom are half-educated and untrained, and these teachers are now teaching in the elitist schools.

Of course, we are very much enatnoured about the school bags. The uniform and the school bags give a very good impression. Very much is said about prestigious school bags which only donkeys can carry, but, unfortunately, the children are asked to carry those bags. People say that these children are developing hump backs because of the school-bags. I do not know the fact.

But one thing is there. There should be neighbourhood schools. There is no point in having schools five kilometres away from the village, the concept of neighbourhood schools should be implemented with all seriousness so that the poor people can send their children to the nearest school.

The social awareness should be created that education of the girl chiltris a must. As-many people and many documents have pointed out, an educated mother is the greatest asset to the family. An educated mother will think of educating the children.

Employment opportunities should also be improved if you want to promote education because there is a general impression in our society. What is the use of getting educated? What is the use of education if we do not get a job? So, the system of our education and the content of education which we are having now niether give a vocational training nor give the knowledge one should have. Therefore, a sort of disinterest is there on this account. The vocational education has to the combined probably with the primary education. This sort of experiment was tried by late Shri C. Rajagopalachari for some time in the united Madras State. That was later on given up as arrold concept. But I still feel that at the primary level vocational education-cum-Formal education given simultaneously will be more useful, especially for the rural children and the children of the poor so that their vocational skills can be improved through this type of education.

I don't think that our schools should be handed over to the police in the name of compulsory education. I for one feel that education should be a matter of joy, especially for the child, and the child should jump with joy to go to school to learn. It should not be under compulsion. Somehow the system should so change that the child should feel happy in the class and in the school as if he is playing there and he is not there under any duress.

Education need not be a sterile type of education as we are seeing it today. Nowadays, education means cramming up and then vomitting it in the examination. This type of examination is neither useful to the child nor

to the society. The content as well as the extent of education should improve. Only then can we achieve what we want in the field of education. Thank you.

श्री भरेश यादव (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, आज शिक्षा पर जो संकल्प हमारी बहन लाई है मैं उसके समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं और एक बात कहने के लिए कि इसमें शिक्षा पूरे देश में आवश्यक है और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए आवश्यक शिक्षा के लिए इस संकल्प को विचारार्थ आज वह लाई है और अगर वह खुद सदन में मौजूद रहकर सारी चर्चा में भाग लेती तो मैं समझता कि इस विषय को, इस संकल्प को लाने वाली खुद गंम्भीरता से लेती हैं। लेकिन संकल्प का अभाव इच्छा शक्ति के अभाव के चलते संविधान के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद-45 में इसे लाया गया कि राज्य इसे संविधान के प्रारम्भ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। यह संविधान के निर्माताओं ने संविधान में उद्धृत किया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट पालिसी में और आज तक इसे पूरे देश में लागू नहीं किया गया। अभी भी देश की जो आधी आबादी महिलाएं हैं सिर्फ 59 परसेंट वह साक्षर है और जो इस देश में पुरुष हैं उनकी संख्या मात्र 58 परसेंट साक्षर हैं। इस देश में आजादी का पचासवां वर्ष हम मना रहे हैं। अगर यही साक्षरता का हाल 50 वर्ष में रहेगा तो आने वाले और 50 वर्ष लग जाएंगे। जबकि अगर प्रयास इसी तरह का जारी रहा तब सभी साक्षर हो जाएंगे। निरक्षरता अंधकार है, साक्षरता प्रकाश है, ज्ञान है। आज सबसे अधिक निरक्षर लोग गांव में निवास करते हैं और सभी इस बात को जानते हैं कि भारत गांव का देश है और भारत का गांव आज 70 परसेंट निरक्षर है। अगर भारत का गांव ही निरक्षर रहेगा तो कृषि का विकास कैसे होगा। हम मेहनत, मशक्कत मजदूरी करने वाले आम लोगों के जीवन में अनाज देने वाले गांव के किसान हैं और वही आज निरक्षर रहेगा तो आधुनिक तकनीक से खेती करने के नए-नए तरीके इजाद हुए हैं, वह खेती कैसे कर सकता है। उपसभाध्यक्ष महोदय, यह एक गंभीर सवाल है और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। चूंकि इसे गंभीरता से लिया गया है और हमारे माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री यहां मौजूद हैं, मैं इस बात को समझता हूं कि कम से कम आप इसे गंभीरता से लेंगे और आगे आने वाले समय में आप संकल्प लेंगे इस सदन के माध्यम से कि कितने वर्ष के भीतर हम इस देश के सम्पूर्ण लोगों को साक्षर कर देंगे। हालांकि हमारे कई विद्वान साथियों ने कई बार महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया है और कहा है। लेकिन मैं भी उसमें जोड़ना चाहता हूं कि आज हम शिक्षा को कैसे लेते हैं। आज देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग, बच्चे गांव से आते हैं और गांव में मवेशी चराने वाले, भेड़ चराने वाले, बकरी चराने वालों की संख्या ज्यादा है, क्योंकि उनके पेट को अन्न नहीं है, उनके परिवार को खाने का साधन नहीं है। तो वह अपना तो श्रम करता ही है और श्रम करने में उतनी मजदूरी नहीं मिलती है कि अपने बच्चे के लिए स्लेट खरीदें, पेंसिल खरीदें और उनके बच्चे स्कूल जाएं।

इसीलिए ऐसा करना पड़ेगा जैसा कि एक अभियान, एक आन्दोलन इस देश में चेचक के टीके लगाने के लिए चलाया गया और पल्स पोलियो के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है और उसकी सफलता का प्रतिशत बहुत ज्यादा हैं साक्षरता मिशन के बारे में टी॰वी॰ पर सिर्फ दिखाने से काम नहीं चलेगा बल्कि इस पर गम्भीरता से सोचना पड़ेगा। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज साक्षरता के नाम से जो अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है, जिस भी संख्या की तरफ से चलाया जा रहा है, क्या उस पर ईमानदारी से अमल किया जा रहा है, इस बारे में सोचना पड़ेगा। उसे एक खेल-कूद और मनोरंजन का माध्यम बना लिया है? जहां तक मैं देखता हूं इसे गम्भीरता से नहीं लिया गया है। अगर गम्भीरता से ले लिया गया, सभी मां-बहनों को हंड्रेड परसेन्ट शिक्षित कर दिया गया तो पूरे देश में एक चीज रुक जायेगी और वह है समाज का शोषण। जो कुछ एलिट्स लोग बहुतायत लोगों का शोषण करते हैं, अपनी गिरगिट की भाषा से शोषण की चक्की चलाते हैं, वह नहीं चलेगी। इसका एक कारण और भी इस देश में है। अंग्रेज इस देश में अंग्रेजियत छोड़ कर चले गये, इस संबंध में कल ही चर्चा हो रही थी। आज लोगों को अंग्रेजी में इतना इन्टरेस्ट नहीं लगता है जितना कि मातृभाषा में लगता है। हमारे हिन्दुस्तान की जो भी मृात भाषाएं हैं, राष्ट्र भाषा है उसमें बच्चों का जो गर्व है, प्यार है वह अंग्रेजी भाषा से नहीं हो सकता है।

अंग्रेज यहां पर अंग्रेजी की एक छाप छोड़ कर चले गये हैं। हम आजादी के पचासवें वर्ष में भी उस छाप को क्या हटा पायेंगे? यह देश निश्चित तौर से विकास तभी करेगा जब कि इस देश में अपनी भाषा में बोल रहे थे और हमारे हिन्दुस्तान के लोग अपनी भाषा में नहीं बोल रहे थे। क्या यही देश का गौरव है, क्या यही देश का स्वाभिमान है? विदेश से चीन के राष्ट्रपति हमारे यहां मेहमान बन कर आते हैं और गर्व से अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं और

हम अपनी मातृभाषा का प्रयोग इस भय से नहीं करते हैं कि हमारी प्रतिष्ठा चली जायेगी, हमारा अपमान हो जायेगा और हम छोटे समझे जायेंगे। जब तक सभी राजनेता संकल्प नहीं करेंगे और मन से, ईमानदारी से, लगन व इच्छा शक्ति से इस बात का प्रयास करेंगे कि पूरे देश में साक्षरता आनी चाहिए तब तक पूरे देश में साक्षरता आने वाली नहीं है।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं कुछ बातें और जोड़ना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस देश में गांव के बच्चे हैं और उनको काम से तथा व्यवहार से जोड़ना पड़ेगा। बिहार के माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक कंसेप्ट चरवाहा विद्यालय का दिया है। लोगों ने पता नहीं क्यों उसे गलत समझा? उसे लोगों ने कैसा भी समझा हो, लेकिन उस कंसेप्ट को, उस विचार को गम्भीरता से पूरे देश में लिया जाना चाहिए। वह कंसेप्ट क्या था, वह विचार क्या था? भेड़ चराने वाले, बकरी चराने वाले, गाय चराने वाले, बैल चराने वाले और हमारे जो मवेशी चराने वाले बच्चे हैं, वे चरवाहा विद्यालय में जाएं। वहां उन्हें दिन का भोजन दिया जायेगा, वे मवेशियों को भी चरायेंगे और साथ-साथ उन्हें वहां पर पढ़ाई व साक्षरता का ज्ञान भी दिया जायेगा। जो क, ख, ग नहीं जानता है, उसे क, ख, ग, का ज्ञान दिया जायेगा और उसे साथ में तकनीकी जानकारी भी दी जायेगी और जो गांव में खेती करते हैं वह जानकारी उनके काम में भी आयेगी। इसलिए इसे ईमानदारी से लागू करना चाहिए।

जब तक हम गांव में गाय-भैंस, मवेशी चराने वाले बच्चों को शिक्षा से नहीं जोड़ेंगे तब तक पूरे देश की निरक्षरता को दूर नहीं कर सकते हैं। इसलिए गांवों के बच्चों को भी इस शिक्षा से जोड़ना चाहिये और गांव के मवेशी चराने वाले बच्चों की तरफ हमें ध्यान देना चाहिये। माननीय सदस्य श्री मार्गबन्धु ने एक अच्छी बात कही है कि हमारे यहां शिक्षा के दो स्तर हैं- एक गरीब का बेटा बिना छप्पर के स्कूल में पढ़ने जाता है और दूसरा अमीर का बेटा-बेटी कोट-पैंट व टाई लगाकर पब्लिक स्कूल में पढ़ने जाता है। हमारा गरीब बच्चा उस अमीर बच्चे को देखता है जो पब्लिक स्कूल में पढ़ने जाता है। इन पब्लिक स्कूलों को प्राइवेट संस्था के लोग चलाते हैं। वहां सौ, दो सौ, चार सौ, पांच सौ, हजार या दस हजार तक की फीस दी जाती है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इस देश में शिक्षा के दो स्तर हैं। एक तरफा जो बच्चे गरीब हैं उनके लिए हम क्या दे रहें हैं और जो बच्चे अमीर है उनके लिए क्या दे रहे हैं? क्या शिक्षा में सुधार नीचे से नहीं लाया जा सकता है? हां, हमें इसमें नीचे से सुधार लाना पड़ेगा। जब तक हम शिक्षा में सुधार नहीं लायेंगे, पूरे देश में पब्लिक स्कूलों को बन्द नहीं करेंगे, जब तक गरीब लोगों के बच्चों का स्वाभिमान नहीं जगायेंगे तब तक उस गरीब बालक को यही लगेगा कि वह बेकार स्कूल में जा रहा है, साकार वही स्कूल है जहां अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। उस बच्चे को लगता है कि सही शिक्षा वहीं दी जा रही है। इसलिए हमें पूरे देश में एक साथ सभी पब्लिक स्कूलों को बन्द करना पड़ेगा। इसके लिए जरूरी है कि शिक्षा की जो ये तीन सूची हैं राज्य सूची, समवर्ती सूची और केन्द्रीय सूची, शिक्षा को समवर्ती सूची में रखकर पूरी की पूरी केन्द्रीय सूची में ले आयें। पूरा देश एक है, हम सभी लोग साक्षर हो जायें इसके लिए जरूरत है कि एज्यूकेशन को, शिक्षा को हम केन्द्रीय सूची में शामिल करें। पूरे देश में शिक्षा एक समानान्तर होनी चाहिये। जहां तक भाषाओं का सवाल है, इस देश में भिन्न-भिन्न भाषाएं हैं, इसको कोई टुकरा नहीं सकता है। इसलिये हमें एक भाषा पूरे देश में लागू करनी चाहिये और उसके अनुसार ही पूरे देश में एज्युकेशन होनी चाहिये। इसके साथ ही मैं। केपिटेशन फीस की बात भी कहना चाहूंगा। पूरे देश में जिन लोगों के पास पैसा है वे लाख या दस लाख देकर तकनीकी विद्यालयों में जा रहे हैं। क्या यह दोहरी व्यवस्था नहीं है? इस देश में एक ही व्यवस्था होनी चाहिये। पूरी शिक्षा में जो भ्रष्टाचार है उसको समाप्त करके हम सदाचार को लायें, तभी हम इसको सही शिक्षा कह सकते हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करना चाहता हूं कि शिक्षा का जो एक सेलेबस है, जो एक कोर्स है वह पूरे देश में एक जैसा ही होना चाहिये तभी सारे देश में एक समान शिक्षा लागू हो सकती है। अंत में मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान, चूंकि सदन में मौजूद हैं, इस ओर दिलाना चाहता हूं कि सभी संस्थाओं का सहयोग लेकर पूरे देश में एक साक्षरता का अभियान चलाया जाये, एक संकल्प लिया जाये कि हम एक वर्ष में, दो वर्ष में या दस वर्ष में देश में सभी नागरिकों को साक्षर कर देंगे।

पूरी इच्छा शक्ति से जब हम इस संकल्प को लेंगे और ईमानदारी से इसे लागू करेंगे तभी सही साक्षरता लागू हो सकती है अन्यथा, हम आजादी की पचासवीं वर्षगांठ मना रहे हैं लेकिन हमारी शिक्षा का प्रतिशत कितना है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर हमारी बहन संकल्प लाई हैं और मैं इसका पूरा समर्थन करता हुं और आशा करता हुं कि इसे सरकार और सदन गंभीरता से लेगा और पूरे देश को साक्षर करने का संकल्प भी पारित करेगा और

हमारे संविधान के निर्माताओं ने अपने दिलों में जो सपना संजोया था कि आजादी के मात्र दस सालों के भीतर पूरे देश में अनिवार्य शिक्षा लागू करेंगे, उसको पूरा करेंगे। लेकिन आजादी के उन दीवानों और अपने देश के उन महान नायकों का सपना आज तक भी पूरा नहीं हुआ है। हम सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि वे कम से कम अपने देश के उन महान नायकों का सपना पूरा करने का प्रयास करें और पूरे देश को साक्षर करने का संकल्प लें जिससे देश का मान-सम्मान बढ़े। इन शब्दों के साथ आपने मुझे जो बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

PROF. SAIFUDDIN SOZ (JAMMU AND KASHMIR): Mr. Vice-Chairman, what prompted me to present some ideas here is what happened in the Eighth Lok Sabha when I introduced a Bill. I had introduced a Bill to abolish the private schools. Some of them are called public schools, but essentially they are private schools. I never understood this. I don't see any good public school in its real sense either in Delhi or Madras or Bombay or Srinagar. These are private schools, commercial institutions. I had introduced a Bill to abolish all private and public schools. Today I have no intention to speak. By chance I felt to speak on the Resolution introduced by our sister and supported by Prof. Naunihal Singh, Mr. Naresh Yadav and others. Private Members' Bills or Resolutions have no importance. I will not raise this issue. I had raised it in the Lok Sabha in one of the sessions. I had raised it deliberately at that time for want of quorum. The Resolutions carry no importance at all. They do not attract attention. But I cannot commit that mistake here because I have now become a little wiser. Private Members have to pass through a mill, then they get this chance. In fact, I could not discuss my Bill in the Lok Sabha. Fortunately, the senior leader, a man of vision, Mr. Bommai, is here. So, it is a rewarding experience for me to say certain things here.

Before I present two or three points in my mind, I would like to point out to Mr. Bommai that it is a legacy that we have miserably failed in education. In fact, education is basically called development which has no importance in the scheme of things. Today I raise a question. It is not a question but an appeal to Bommai Sahib. We have discussed the issue of education a number of times during the past 50 years. We have never cared to raise the Constitution in our hands and salute it. We were committed to do something in 1960. But we could not do it. Today no measure is taken. The hon. Minister of Human Resource Development should invite all parties. Some people, who will be nominated by the parties, should sit hours together on this question of universalisation of education. I support his Resolution. There are so many Resolutions like this. You must go into this question why we have miserably failed in providing elementary education. We promised-by 'we' I mean the leaders, the founding fathers—we pledged ourselves to the nation that we would universalise education by 1960. Now it is 1996. When Mrs. Sheila Kaul was the Minister of Education I was a member of the Consultative Committee. She made a statement from which I differed at that time. It was again in the beginning of the Eighth Lok Sabha. She made a statement that by 2000 we would completely universalise education. I differed from her statement at that time. It was a wrong statement. If she had made a correct statement, we would not be discussing this Resolution here today.

It was a wrong statement. Of course, that wrong was not committed by her. That is how so many reports and documents move and so much material is produced and so much wastage is there. I had raised a simple question at that time. Now I put that question to the hon. Minister of Human Resource Development. She made a statement that all would get into schools by 2000.I said that it was a wrong commitment because at that time drop-out rate in primary schools was 68 per cent. This figure was supplied by the NCERT. I said, "The drop-out is so high. You will be getting in some students but some would be moving out also. Those who move out would be outnumbering the students who would be coming in." It is a legacy for the present Minister of Human Resource Development. I would like to make one suggestion. Let us sit together for one day or two days with some educationists, essentially they should be public men. We come from the public to

redress their grievances. We must sit together and go into this question. It is this sector where we have failed. Without going into the details. I would say that the constitutional commitment was up to 1960. Our sister says upto 14 call it elementary education, call it basic education in a broader sense or give it the title of universalisation of education. But we have failed miserably. We prepare a plan every five years. But We have never paid attention to this problem. Therefore, we have to study it again and again and come to some conclusion. Mr. Yadav was saying, *"Isko gambhirta se nahi liya jata."* Yes, I also say it. It has never been considered a very serious problem. If something is seriously done, then only can something be achieved. But it has not been taken up seriously at all. When the Consultative Committee meets, it has an agenda. There is a cup of coffee or tea. Then we buzz off. Nothing has been seriously discussed and achieved. This is my suggestion. Let us discuss this topic very seriously. I will not go into this question, i.e. how education is basic to all developments. This is a theoretical proposition. I know it as a student of economics. I know how education is basic to all developments. It may be steel. It may be copper or it may be exploitation of resources. It may be any department. But education is basic. Education is the one field which has not received any attention, any significant attention. I am not adding anything for his information. I cannot add anything for the information of the HRD Minister. He is a man of vision. He is very senior. He has seen it. The Government school sector is in a shambles. It is an insult to the genius of this country. Mr. Yadav has said this. Prof. Naunihal Singh has said this and our sister has said this. In fact, in this House there is a total consensus on this question. How can the Government school sector become viable? Sons and daughters of bureaucrats go to private schools. Sons and daughters of politicians go to private schools. Children of clerks go to private schools. It is the downtrodden people, the majority people, who suffer. Therefore, If I have a position of strength in this country, in this House, I would go to the whole hog with Mr. Yadav and say, "Abolish private schools and public schools. DPS may be a good school. But are its doors open to all? I know how people struggle to get into it. Kids coming from a far-flung area, are put to tests. Even before learning anything they are put to tests. The doors of that school are not open to the general public. It is the common man who is suffering. It is the common man who pays tax. If you go through the tax system, you will see, ultimately it is the common man who pays.

Ultimately, it is the common man who pays. He is not receiving any education because the Government schools are in a shamble. See the percentage of results. See the equipment that is avilable there. Some of the schools do not have teachers. In UP, the schools are locked. It must be worse in Bihar and in other parts of the country. The children may come to school. But there is no teacher. They are engaged in their own business. They come at the end of the month to collect their salary. The Government school sector will never thrive. All this May appear to the hon. Chairperson as tall talk from a Member here. But the fact is that the Government school sector is in a shamble. It cannot be improved unless we close down public and private schools. You cannot close down public schools because they are run by men and women who have a clout. They have vested interest in these schools. I say this with anguish because we are not able to improve the schools in the Government sector. All the funds that are being given are going waste. I want to raise another question here about our universities. The learned HRD Minister must be knowing about this. Recently, two Bills were passed by the house without my intervention. My intervention would not mean anything. I wanted to intervene in the case of the Urdu University Bill. I wanted to say that if you were to import some training in crafts, I would accept the Bill. But if you have to impart instructions for Masters Degree through Urdu, I would say, it would fail. But the Bill is not before me. It has become common place to support all these things. Whether it is Urdu University or Hindi University, I do not mind. But I would support institutions which would produce stenographers, carpenters, weavers, etc. Give the person an education which will

support him outside the university. Bommai saheb must be knowing about this. You will not be able to absorb the people who will be educated from these universities. You will impart education through Urdu. The Vice-chancellor will say that all the English books will have to be translated. Translation is not always equal to the original text. Every language has its own genius. The effort of the Nizam of Hyderabad had failed miserably. It is not a question of giving instruction through Urdu. I have raised a broader question here. Let me make a claim here. It may be contested at a later date. Most of the funding of universities goes waste. That money should be given to the Government schools. This will not cause any harm to the universities. Let me give you an example. Every university competes with other universities. It wants more buildings. It wants funds for proliferationof subjects. I had raised a question whether it was necessary for all the universities to have subjects like Urdu, Hindi, Persian, Arabic and Sanskrit. You can give scholarships to students who want to learn Persian, who want to learn Arabic or who want to learn Sanskrit. They can go to reputed institutions where excellent education in these lenguages is available. Why don't you have a department for science in these universities? Why don't you impart education in social science which is very relevant, to the society? How many universities produce people who will help the society? How many universities produce research work which is useful to the society? Unfortunately, it is not only in my State, but in every university, we have a Persian department. You may have only one student. But you want to have it because somebody will be annoyed. I have nothing against Urdu or Hindi or Sanskrit.

But I am telling you that in every department the heads of departments and the teachers vie with each other and ultimately in Urdu, Persian and Hindi-I have no fear that I will be contradicted — there are no topics for research. I have made some survey and I found that there were no topics on which you could do research and it means that a lot of common people's money is going waste. But let us promote science, let us promote social sciences, so for languages, whatever be the language, even the *rashtra bhasha,* we can send students given them a very high stipend— to institutions which are reputed and where the medium of instruc-tion is of a high quality. University education, as everyone knows, receives a lot of funding. Already primary education is suffering. In fact, education has the least budget. I do not know the latest figures. During the Eighth Lok Sabha I had *pucca* figures, it was three per cent of the national income. But now it must be four per cent; I do not know. But actually, it depends: sometimes it is double counting. Since I am not an expert, I have to be careful. I must consult somebody to tell you what percentage of national income goes to education and what percentage of that funding goes to university system and what portion of that funding goes waste-down-the drain. Primary education and sub-dialect school education are in a shambles. But there is no funding for elementary school education. There is no system of instruction, there is no system of inspection. In a big Stake like U.P. where thirteen and a half crore people live, what is the position of primary schools? I do not know where the latest survey is. I have no idea but the fifth survey must be there. The fifth survey must be available. I want to know the latest position about the status of elementary education in U.P. and other States. Somebody must go into the question of wastage in the university system and we must go in for greater funding in elementary school education. I want to raise this broader question through you, Mr. Chairperson. I hope the hon. Minister will invite, not me, but others who took part in the debate, for a greater discussion, not necessarily today but whomsover he wants to invite; they can sit for a longer period of time. Merely discussing and taking part in the debate but arriving at no decision is not good. This august House is the last forum for the people of India; there is nothing beyond the Parliament of India and if we also here discuss for the sake of discussions, it will lead us nowhere. We shall be talking to our constituents untruth and our people are now conscious. They are looking for guidance. We cannot give guidance unless we have a say which is purposeful and the

H.R.D. Minister organises a discussion of such nature so that we are able to take a decision. Thank you very much.

SHRI NILOTPAL BASU (West Bengal): Sir, it is a pity that a resolution like this is being discussed in the atmosphere that we have here today and this is an ample testimony as to why we have to discuss such things. it is really an issue of national shame, I should say. But the problem is with the background in which our Constitution was framed and the fact that in the Constitution itself the issue of right to education could not be included as a Fundamental Right but was included in the Directive Principles as Clause 45.

In the general background of decolonisation that was going on all over the world, the leaders of the newly liberated India considered that the Government of free India would not be having enough resources to immediately make the right to education as a justiciable right in the sense that the Government could be penalised for violating this right. It is in this background that the makers of our Constitution incorporated 'educaton' as a part of the Directive Principles of the State Policy. They hoped that the new nation, the free nation, would realise the importance of education, particularly the importance of elementary education and within 10 years it would reach a stage where, for all practical purposes, education would become a fundamental right. The difficulty has been that over' the years the basic philosophical approach to education has been misplaced. Education is essentially considered as a welfare activity. Investment in education has never been considered as productive investment. When we go through the philosophy of education, through the great debates that took place in the Parliaments of developed countries of Europe and America, it would become clear that they considered education a *sine qua non* for development and industrialisation and this they realised as far back as the 18th century itself. When we started this debate in our country, the whole question was turned upside down. When you look at the pattern of investment in education, from the First Plan onwards until the Sixth Plan, you will find that there is a gradual diminition in the allocation of funds for education as a whole. Even sectorally, the proportionate allocation for elementary education has come down as opposed to higher education. In the beginning of the 50's a number of technical centres were set up—JTIs, Polytechnics and other centres of excellence. We discussed in the morning today the issue of IITs. We have been suffering from the British hangover which believes that education will percolate down to the grassroot levels. It believes that education will become available to the grassroot-level communities through some vehicles. What will be these vehicles? It is considered that some small exclusive elite sections will carry education to the grassroot-level communities. The question of providing direct access to people to education was not at all considered. We.now of the infamous educational package offered by Lord Macaulay, who was the leading theoretical inspiration behind the British educational policy. He said that education would filter down through a small elite section who will take education, enlightenment, to the grassroot communities. This basic philosophy of filtering of education as opposed to provision of direct access to people to the educational opportnities was never reversed. We have continued the same colonial legacy even after independence.

Therefore, on the one hand we see that the kind of importance, thrust and emphasis that should have been given to education, was not given. On the other hand.whatever allocation was made for education, it was loaded against elementary education; it was in favour of higher education. The point is that higher education cannot develop unless it has a wider foundation of elementary education, therefore, what we find today is, as Bommai Saheb was also telling us in- the morning, that we are spending one lakh of rupees per student in an I1T, whereas that student pays only Rs. 1,500 and we are now proposing to increase it to Rs. 15,000. And, what is the result? The result is that 60% of the students that are coming out of IITs, are going abroad. The public investment that we are making in higher education is not coming back to the society. The community at large is not being benefited.

So, the problem is that the investment doesn't really become a vehicle for unleashing the productive forces, for strengthening the productive forces. The Chairman also very jocularly, but perceptively, remarked that we are subsidising the Americans. That has actually happened. That is the problem. Then, even with the investment that we are making in elementary education, what is happening? I have a background of the student movement. I was studying in an engineering college. What we used to see was that the students, after coming out of the whole process of education for five years in a cosmopolitan city, were totally detatched from the milieu that they were coming from. They wouldn't go back to their villages. They would not contribute to the communities they were hailing from. Therefore, we see that there is utter mis-utilisation of resources.

Therefore, unless there is a basic reorientation in the whole concept as to what for we are investing and whether the investment is actually contributive to the national economy, our approach will not change. There is no dearth of high thinking on education and a very rich education material in the country. There have been three major Education Commissions. Dr. Murty was mentioning about the most important one, the Kothari Commission which produced a very voluminous report. In fact, it was at the time of our freedom struggle itself that the All India Congress Committee at the behest of Mahatma Gandhi, in its Haripura session in 1938 appointed a National Education Commission under the chairmanship of Dr. Zakir Husain.

Sir, so many recommendations are there and we see that everywhere the thrust was on widening the base of our education system, our educational process.

Before I proceed further, Sir, do you think I am crossing the limit? 1 can continue on the next day. I can leave it at that.

श्री नीलोत्पल बसु : अगर आप चाहते हैं तो दूसरे दिन हम कांटीन्यू कर सकते हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री रामदेव भंडारी) : अभी एक-डेढ़ मिनट हैं 5:00 बजने में। आप अभी एक-डेढ़ मिनट बोल लीजिए।

श्री नीलोत्पल बसु : लेकिन एक मिनट में तो समाप्त नहीं होगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री रामदेव भंडारी) : अगले दिन आप कांटीन्यू करेंगे, जिस दिन यह आएगा।

SHRI NILOTPAL BASU : So, the whole approach, therefore, has to be re-oriented. That is the basic question. All the policy-makers have stressed one point that investment in education will have to be linked with our Gross National Product (GNP).

At least, six per cent of the GNP has to be invested in education. But the problem, particularly from the middle of the eighties is that the rules of the market place have also started to dominate the educational thinking and the educational process and education has been totally "commodified". So, I leave it here.....

SHRI RAMACHANDRAN PILLAI: To the market forces !

SHRI NILOTPAL BASU : No, no. Not to the market forces. So, I leave it for the time being.

उपसभाध्यक्ष (श्री रामदेव भंडारी) : इस विषय पर फिर जब चर्चा होगी, तब आप बोल लीजिएगा। कोहली साहब का भी नाम लिखा हुआ है। उनको भी उस दिन बोलने का मौका मिलेगा।

So, I adjourn the House till 11.00 A.M. on Monday, the 2nd December, 1996.

The House then adjourned at one minute past five of the clock till eleven of the clock on Monday, the 2nd December, 1996.